A Daily News Magazine
इंदौर
शुक्रवार, 26 दिसंबर, 2025
इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 11 अंक 89, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

04 - बांग्लादेशः अल्पसंख्यकों की पीड़ा व लोकतंत्र की परीक्षा

05 - सम्यक सांस्कृतिक सोच के प्रतीक पंडित सीताराम त्रिपाठी

06 - अटलजी की जयंती सुशासन दिवस पर सांसद खेल महोत्सव...

07 - राजनैतिक दलों की बैठक अनमैप मतदाताओं को 02 जनवरी 2026 से...

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

राजनीतिक क्षेत्र में भगवद्गीता लोकप्रिय होने की वजह क्या है?

सान्या ढींगरा

क्या अफजल खान को मारकर शिवाजी ने कोई पाप किया था? यह सवाल बाल गंगाधर तिलक ने 12 जून 1897 को शिवाजी जयंती के अवसर पर आयोजित एक सभा में पूछा था। अफजल खान आदिलशाही सल्तनत का एक शक्तिशाली सेनापति था, जिसे लगभग ढाई सौ साल पहले शिवाजी को कुचलने के लिए भेजा गया था। उसी अफजल खान को शिवाजी ने उस मुलाकात में मार दिया था, जो समझौते के लिए होनी थी। तिलक ने कहा कि यह तय करने का जवाब कि वह हत्या पाप थी या नहीं, महाभारत में मिलता है। उन्होंने कहा, 'गीता में श्रीकृष्ण का उपदेश है कि अपने ही गुरुजनों और रिश्तेदारों तक को मार देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा के बिना काम करता है, तो उस पर कोई दोष नहीं लगता।'

तिलक ने भारतीयों से अपील की कि वे किसी बड़े उद्देश्य के लिए फिर से कानूनी बंधनों और नैतिक संकोचों को तोड़ें। उन्होंने कहा, 'अपनी सोच को मेंढक की तरह सीमित मत करो, बल्कि श्रीमद्भगवद्गीता के ऊंचे वातावरण में प्रवेश करो और महान पुरुषों के कर्मों को देखो।'

19वीं सदी के आखिरी वर्षों और 20वीं सदी की शुरुआत तक, भगवद्गीता, जो महाभारत के एक लाख श्लोकों वाले महाकाव्य में 700 श्लोकों का ग्रंथ है और जिसे सदियों से हिंदुओं में सम्मान मिला है, क्रांतिकारियों के लिए एक तरह का ताबीज बन गई थी। यह राजनीतिक क्षेत्र में, खासकर हिंसक कार्रवाई के लिए, धार्मिक और दार्शनिक आधार बन गई। तिलक से लेकर अरविंदो तक, जिन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को हिंसा के बदले हिंसा की रणनीति से हराना चाहा, उन्होंने गीता की अपनी व्याख्या से वैधता हासिल की।

करीब एक सदी बाद, भगवद्गीता फिर से राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र में है। पिछले हफ्ते, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस, बीजेपी नेताओं, और राज्य भर से आए साधु-साध्वियों समेत पांच लाख से ज्यादा लोग कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में गीता के सामूहिक पाठ के लिए जुटे। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने, जो इस कार्यक्रम में शामिल थे ने कहा, 'बंगाल में पिछले तीन साल से गीता का कार्यक्रम हो रहा है। जैसे आजादी के आंदोलन के दौरान, जब देश हिंदू-मुस्लिम मुद्दे पर बंट रहा था, तब गीता ने हिंदुओं को एकजुट किया था, वैसे ही आज बंगाल में हमें फिर से गीता की जरूरत है। बंगाल में हिंदुओं को अपने ही देश में शरणार्थी बनने का खतरा है। इसलिए गीता उन्हें जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि पहली बात तो यह कि हर हिंदू, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो, गीता में विश्वास करता है, और दूसरी बात यह कि गीता कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में कही गई है, जो लोगों को लड़ने की ऊर्जा देती है। गीता ऊर्जा, शक्ति और सही लड़ाई लड़ने का ग्रंथ है।'

कोलकाता से दूर, नई दिल्ली में भी गीता हाल के हफ्तों में भारतीय कूटनीति के केंद्र में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यात्रा पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गीता का रूसी अनुवाद भेंट किया। आरएसएस से जुड़े एक लेखक ने कहा, 'गीता भारत की सबसे शक्तिशाली सॉफ्ट पावर हथियार है। यह पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की आध्यात्मिक पहचान है।'

इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर स्कूलों के पाठ्यक्रम में भगवद्गीता को शामिल करने की मांग की। इस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन्हें 'मनुवादी' कहा। लखनऊ से कुरुक्षेत्र तक, और शिवमोग्गा से हैदराबाद तक, देश भर में बड़े स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें मुख्यमंत्री, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सेवानिवृत्त नौकरशाह शामिल हो रहे हैं। इन आयोजनों में इस प्राचीन ग्रंथ की शिक्षाओं पर चर्चा और पाठ किया जा रहा है।

तो राजनीति में भगवद्गीता की यह वापसी क्यों हो रही है। क्या इसे राजनीतिक और धार्मिक लामबंदी के लिए बढ़ावा देने की कोई सोची-समझी कोशिश है, या यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है? शुरुआत में, संघ परिवार से जुड़े अलग-अलग नेताओं और लेखकों ने बताया कि आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद द्वारा इन कार्यक्रमों को आयोजित करने की कोई संगठित या योजनाबद्ध कोशिश नहीं है। हालांकि, गीता की मुख्य शिक्षा, यानी भारत की सोच आध्यात्मिकता और शक्ति दोनों से जुड़ी है, यही न केवल मौजूदा सरकार बल्कि पूरे संघ परिवार के लिए प्रेरक शक्ति रही है, हरियाणा के एक आरएसएस नेता ने कहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा से लेकर बंगाल और अंतरराष्ट्रीय मंच तक, 'पिछले दस वर्षों में गीता की वापसी इसलिए दिखती है क्योंकि हमारी विश्वदृष्टि गीता से ही निकलती है। गीता का संदेश इतना सरल और स्पष्ट है कि लोग स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जनरेशन जेड, जो साफ तौर पर जीवन में एक खालीपन महसूस कर रही है, अपने आप गीता की ओर बढ़ रही है।'

साथ ही, दशकों से भगवद्गीता की अंतरराष्ट्रीय अपील रही है। परमाणु बम के जनक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भी गीता पढ़ी थी और वह उससे गहराई से प्रभावित थे।' गीता का अंतरराष्ट्रीयकरण और उससे जुड़ा हिंदू आत्मसम्मान का बढ़ना वास्तव में एक लंबा इतिहास रखता है।

मनु पिल्लै ने अपनी किताब गॉड्स, गन्स एंड मिशनरीज में तर्क दिया है कि भारतीय इतिहास की यूरोपीय 'खोज' का एक 'अनपेक्षित परिणाम' यह हुआ कि भारतीयों में अपने इतिहास को लेकर गर्व तेजी से बढ़ा। 1785 में पहली बार अंग्रेजी में अनूदित भगवद्गीता की 'खोज' इसका एक उदाहरण थी। औपनिवेशिक भारत के शुरुआती और प्रभावशाली ब्रिटिश प्रशासक वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि गीता का धर्मशास्त्र ईसाई धर्म की बुनियादी शिक्षाओं से 'सटीक रूप से मेल खाता है।' पश्चिम में भगवद्गीता एक सनसनी बन गई। विद्वानों और दार्शनिकों ने इसे पूर्वी ज्ञान की खिड़की बताया। कृष्ण की केंद्रीय भूमिका को 'अशुद्ध न हुए हिंदू धर्म' के एकेश्वरवाद के प्रमाण के रूप में आगे बढ़ाया गया। गीता की बढ़ती प्रतिष्ठा ने उस समय हिंदू आत्मसम्मान को बढ़ाया, जब अंग्रेज उन्हें मूर्तिपूजा के लिए नीचा दिखाते और अपमानित करते थे। 1907 में, जब तिलक के करीबी मित्र केशव कृष्णाजी दामले ने अलग-अलग जगहों पर गीता पर व्याख्यान दिए, तो जिला मजिस्ट्रेट ने टिप्पणी की, 'यह व्याख्यान बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने इतनी चतुराई से विद्रोह का प्रचार किया कि यह संदिग्ध है कि दंड संहिता उन्हें छू भी पाएगी।' मकरंद परांजपे कहते हैं, 'गीता निस्संदेह वह सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक या धार्मिक ग्रंथ है, जिसका इस्तेमाल भारतीय नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया।क्योंकि उन्हें 'कर्म योग' के सिद्धांत में राष्ट्रीय पुनर्जागरण की कुंजी दिखी।'

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

शरद की सुबह

एक शहर मिला कुछ गीतों का,
कुछ नग्मों का, कुछ गानों का।
एक नज़र मिली उम्मीदों की,
कुछ सपनों की, कुछ क़िस्सों की।
एक ख्वाब दिखा,
एक मोड़ आया,
कहीं नज़र टिकी,
एक शोर आया।
मैं ठहर गया,
रह जाने को,
अपने भाव बताने को।
न जगह दिखी थी कोई ऐसी,
न जाना था ऐसा भी हो सकता है।
जो कहते हैं अँधेरा है,
सिर्फ़ साँपों का बसेरा है,
हाथ पकड़ ले जाता हूँ,
ये शहर उन्हें दिखाता हूँ।
अब मैं भी बात बताता हूँ,
सबको गीत सुनाता हूँ।

— तनुज मिश्रा

क्रिसमस पर दिल्ली की कैथेड्रल चर्च पहुंचे पीएम

● मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हुए, बिशप ने की विशेष प्रार्थना

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के 'कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्प्शन' में क्रिसमस की प्रार्थनासभा में हिस्सा लिया। इस अवसर पर दिल्ली और उत्तर भारत से बड़ी संख्या में आए ईसाई श्रद्धालु गिरजाघर में उपस्थित रहे।

इस प्रेयर मीट में प्रार्थनाएं, कैरल, और दिल्ली के बिशप राइट रेवरेंड डॉ. पॉल स्वरूप की ओर से प्रधानमंत्री के लिए एक विशेष प्रेयर शामिल थी। पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में चर्च की तस्वीरें शेयर की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि मैंने दिल्ली के 'कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्प्शन' में क्रिसमस की सुबह की प्रार्थना में हिस्सा लिया। प्रार्थना में प्रेम, शांति और करुणा का शाश्वत संदेश झलक रहा था।

आशा है कि क्रिसमस की भावना हमारे समाज में सद्भाव और सामंजस्य को प्रेरित करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी थीं। पीएम मोदी ने 'एक्स' पर एक अन्य पोस्ट में लिखा कि शांति, करुणा और आशा से भरे क्रिसमस की सभी को शुभकामनाएं।

कर्नाटक में बस में आग, 10 जिंदा जले

● 30 से ज्यादा यात्री सवार थे, और मौत की आशंका

चित्रदुर्ग के हिरियूर में लॉरी से टक्कर के बाद हादसा

चित्रदुर्ग (एजेंसी)। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बुधवार देर रात स्लीपर बस में टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में बस में सवार 10 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 12 और 17 बताया जा रहा है। हादसा एनएच-48 पर हिरियूर तालुक में हुआ। बस बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में 30 से ज्यादा यात्री थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात 2.30 बजे तेज रफ्तार लॉरी डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से जा रही प्राइवेट कंपनी की सीबर्ड ट्रांसपोर्ट की बस से टकरा गई। बस में तुरंत आग लग गई। उस समय यात्री सो रहे थे। इस कारण उन्हें खुद को बचाने का मौका नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि ज्यादातर यात्रियों ने टिकट ऑनलाइन बुक किए थे। इससे पुलिस को उनके फोन नंबर मिल गए हैं।

बस के ड्राइवर-क्लीनर ने कूदकर बचाई जान

ईस्ट जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रविकांत गौड़ा ने बताया कि बस के ड्राइवर और क्लीनर बच गए हैं, जबकि ट्रक के ड्राइवर-क्लीनर की मौत हो गई है। कई यात्रियों ने बस से कूदकर जान बचाई। घायल यात्रियों को तुमकुरु जिले में शिरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो यात्री गंभीर हैं। पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। वहीं, मृतकों के परिजन को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। हादसे का शिकार हुई बस के ड्राइवर ने पुलिस को बताया है कि उसने सामने से आ रहे ओवरस्पीड ट्रक को देखकर अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हादसे के एक चश्मदीद ने बताया कि वे एक स्कूल बस में बेंगलुरु से दांडेली के लिए निकले थे। उसी समय यह हादसा हुआ। लॉरी अचानक सड़क पार से आई और स्लीपर बस से टकरा गई। स्कूली बच्चों वाली बस के ड्राइवर ने पीछे से बस को टक्कर मारी, दूसरी तरफ मुड़ा और सड़क से नीचे उतर गया। इसके कारण किसी को चोट भी नहीं आई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश के चहुँमुखी विकास की रखी सशक्त नींव : शाह

संतुलित विकास के क्षेत्रीय निवेश सम्मेलनों की श्रृंखला की शुरूआत को बताया दूरदर्शी

भोपाल। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा मप्र के संतुलित विकास के क्षेत्रीय निवेश सम्मेलनों की श्रंखला आयोजित करने की शुरूआत को दूरदर्शी बताया है। उन्होंने कहा कि यह ऐसी शुरूआत नरेन्द्र मोदी जी ने गुजरात के लिये की थी। 'वाइब्रेंट गुजरात' के नाम से इंडस्ट्रियल समिट आयोजित करने की एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित शुरुआत उन्होंने की। इसमें राज्य की राजधानी में बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल समिट आयोजित होते थे और राज्य में व्यापक निवेश आता था। डॉ. यादव ने क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से मध्यप्रदेश के चहुँमुखी विकास की एक मजबूत नींव रखी है।

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती परग्वालियर में 'अभुदय - मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट' में अपने संबोधन मेंकेन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्लस्टर इन्वेंस्टमेंट पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं डॉ. मोहन यादव को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने राज्य के संतुलित विकास के लिए 'क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव' की एक नई और दूरदर्शी शुरुआत की है। मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कॉन्क्लेव आयोजित करने और निवेश के भूमिपूजन का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, वह आने वाले समय में राज्य के संतुलित विकास के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।

आज जो 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश हो रहा है, वह देखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन किसी एक क्षेत्र के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी क्षेत्र की जनता के लिए यह निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि राज्य का संतुलित विकास नहीं होता, तो राज्य आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हर क्षेत्र में अपार संभावनाएँ छिपी होती हैं।जैसे मालवा, ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में कपास लंबे समय से किसानों की प्रमुख फसल रही है, लेकिन उन्हें उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। अब पीएम मित्र पार्क के आने से पारंपरिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ा है और कपास फिर से किसानों के लिए एक लाभकारी फसल बन गई है।

मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता उसका भौगोलिक लोकेशन है। यहाँ से पूरे देश के आधे हिस्से तक बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आपूर्ति संभव है। लेकिन इस भौगोलिक लाभ का शत-प्रतिशत उपयोग तभी संभव है, जब राज्य में सिमेट्रिक इंडस्ट्री विकसित की जाए। दक्षिण से जुड़े जिलों में उद्योग स्थापित हों, दिल्ली से जुड़े जिलों, जैसे ग्वालियर में उद्योग लगेंऔर पश्चिमी क्षेत्रों जैसे धार और झाबुआ में भी औद्योगिक विकास हो। तभी मध्यप्रदेश को अपने भौगोलिक लाभ का वास्तविक फायदा मिलेगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि इसी सोच के साथ यह आयोजन डॉ. मोहन यादव ने किया है। मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ कि उनकी क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिट ने मध्यप्रदेश के चहुँमुखी विकास की एक मजबूत नींव रखी है।

भविष्य के युद्ध के लिए सेना की बड़ी प्लानिंग

● इंडियन आर्मी बना रही है 'ड्रोन फोर्स', ट्रेनिंग शुरू

नई दिल्ली (एजेंसी)। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान से लेकर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तमाम बड़े अधिकारी भविष्य के युद्ध के हिसाब से ही सैन्य तैयारियों की आवश्यकता जाहिर कर चुके हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश में सेनाओं के बीच से इस तरह की चर्चाएं तेज हुई हैं, क्योंकि आने वाले जितने भी युद्ध लड़े जाएंगे, वह अब परंपरागत नहीं होंगे, इस बात में किसी को कोई दुविधा नहीं रह गई है। इसी कड़ी में भारतीय सेना एक पूरी तरह से समर्पित ड्रोन फोर्स बनाने पर काम कर रही है, जो भविष्य की जरूरतों के मुताबिक अपने काम में पूरी तरह से हुनरमंद होगी। भारतीय सेना ने एक मजबूत और समर्पित ड्रोन फोर्स बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। क्योंकि, सेना मान चुकी है कि भविष्य में होने वाले सैन्य संघर्षों में अनमैन्ड एरियल व्हीकल जरूरी है।

19 प्रमुख आर्मी सेंटर में ड्रोन ट्रेनिंग

इसी कड़ी में देश के 19 प्रमुख आर्मी सेंटर में ड्रोन ट्रेनिंग सेटर भी स्थापित किए जा रहे हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी, चेन्नई और गया में ऑफीसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, महू में इंफैंट्री स्कूल और देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में भी तैयार हो रहे हैं। इन केंद्रों में सैन्य अधिकारियों से लेकर जवानों तक के लिए एक सुव्यवस्थित ट्रेनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। वैसे सेना का लक्ष्य है कि 2027 तक उसके सभी जवान बेसिक ड्रोन ऑपरेशन में प्रशिक्षित हो जाएं। इसके लिए वर्चुअल रियलिटी बेस्ड ड्रोन सिम्यूलेटर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ज्यादा सुरक्षित, वास्तविक और किफायती ट्रेनिंग मिल सके।

स्वदेशी ड्रोन के लिए सरकार की पहल

बता दें कि सरकार स्वदेशी ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए ही प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस जैसे प्रोग्राम भी चला रही है। इसी के तहत नागास्त्र-1 लोइटरिंग म्यूनिशन जैसे स्वदेशी प्लेटफॉर्म पहले ही शामिल किए जा चुके हैं, जो सटीक और आक्रामक हमलों में माहिर हैं। साथ ही साथ दुश्मन के ड्रोन से निपटने के लिए भी भारतीय सेना अपनी ताकत बढ़ा रही है। इसके तहत डी4 एंटी ड्रोन सिस्टम, सक्षम और भार्गवास्त्र जैसे स्वदेशी सिस्टम विकसित किए गए हैं, जो दुश्मन के ड्रोन का पता लगाएंगे।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 27 °c न्यूनतम 23°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

पहले एक परिवार की मूर्तियां लगती थीं आज हर विभूति को सम्मान

लखनऊ में बोले प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का किया इनॉगरेशन

लखनऊ (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पं. दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण करके पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने कहा- पहले एक परिवार की मूर्तियां लगती थीं, आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा है। पहले एक ही परिवार का गौरव-गान होता था। भाजपा ने हर किसी के योगदान को सम्मान दिया। मोदी ने ये भी कहा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिल्ली के कर्तव्य पथ है।

अंडमान में नेताजी ने जहां पर तिरंगा फहराया, वहां उनकी प्रतिमा है। कोई नहीं भूल सकता है कि अंबेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास किया गया। दिल्ली के शाही परिवार ने इसे मिटाने का प्रयास किया। यहां सपा ने भी ऐसा किया, लेकिन भाजपा ने इसे मिटने नहीं दिया।

प्रेरणा स्थल पर 65-65 फीट ऊंची दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियां लगाई गई हैं। हर एक प्रतिमा 42 टन वजनी है। प्रेरणा स्थल 65 एकड़ क्षेत्र में 230 करोड़ रुपए की लागत से बना है। साल 2022 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। दिल्ली के एक शाही परिवार ने बाबा साहब आंबेडकर का जिक्र इसलिए नहीं किया कि कहीं उनके महत्व में कमी न आ जाए। प्रदेश में यही काम सपा ने किया। कांग्रेस ने बीजेपी को अछूत बनाए रखा।

पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लिए सीएम योगी को बधाई दी

पीएम मोदी ने कहा- साथियों आज इस पावन दिन महामना मालवीय, अटलजी व महाराज बिजली पासी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज मुझे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन का अवसर मिला है। यह स्थल उस सोच का प्रतीक है। जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल, अटलजी की विशाल मूर्तियां जितनी ऊंची हैं, उनके मिलने वाली प्रेरणाएं उनसे ऊंची हैं। अटलजी ने लिखा था- नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन-मन, जीवन को शत-शत आहुति में, जलना होगा, गलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा। मैं लखनऊ, यूपी और पूरे देश को इस स्थल की बधाई देता हूं। जैसा कि बताया गया है कि जिस जमीन पर यह स्थल बना है। उसकी 30 एकड़ जमीन पर कई दशक जमीन पर कूड़े-कचरे का पहाड़ जमा था। 3 वर्षों में इसे खत्म कर दिया।

कंबोडिया में हिंदू देवता की मूर्ति तोड़े जाने पर भड़का भारत

● कहा-ऐसे अपमानजनक कृत्य से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष के दौरान एक हिंदू देवता की मूर्ति तोड़े जाने पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को कहा कि ऐसे अपमानजनक कृत्य से दुनियाभर के श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं। भारत ने दोनों देशों से सीमा विवाद को बातचीत और कूटनीति से सुलझाने का आग्रह किया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि उन्होंने हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा विवाद वाले इलाके में एक हिंदू देवता की नई मूर्ति को तोड़े जाने की खबरें देखी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू और बौद्ध देवताओं की पूजा पूरे क्षेत्र में लोग बड़ी श्रद्धा से करते हैं। यह हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। जायसवाल ने मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि क्षेत्रीय दावों से परे, इस तरह के अपमानजनक कृत्य दुनिया भर के श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा, यह नहीं होना चाहिए। भारत ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। यह घटना थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच हुई है। दोनों देश इस इलाके पर अपना-अपना दावा करते रहे हैं, जिससे कई बार तनाव की स्थिति बनी है।

एक करोड़ का ईनामी नक्सली गणेश उइके ढेर

● सुरक्षा बलों ने 5 साथियों का भी किया एनकाउंटर ● ओड़िशा के कंधमाल जिले में मिली बड़ी सफलता

गणेश उइके

कंधमाल (एजेंसी)। ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जंगलों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने शीर्ष नक्सली नेता गणेश उइके समेत कुल चार नक्सलियों को मार गिराया है। गणेश उइके नक्सली संगठन की केंद्रीय कमेटी का सदस्य बताया जा रहा है और लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गणेश उइके ओडिशा में नक्सली गतिविधियों का मुख्य संचालक था और उस पर सरकार की ओर से 1.1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया गया था। उसकी मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। यह अभियान घने जंगलों वाले क्षेत्र में चलाया गया, जहां नक्सलियों के छिपे होने की आशंका थी। अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही सुरक्षाबलों की टीम संदिग्ध इलाके में पहुंची, वहां मौजूद नक्सलियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से कुछ देर तक फायरिंग होती रही, जिसके बाद मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। मारे गए नक्सलियों में गणेश उइके के अलावा 5 अन्य शामिल हैं, जिनमें दो महिलाएं भी बताई जा रही हैं। फिलहाल बाकी नक्सलियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ स्थल से हथियार, गोला-बारूद और नक्सली साहित्य बरामद किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह इलाका नक्सली गतिविधियों का अहम केंद्र रहा है।

भारत ने 'घातक' मिसाइल के-4 का किया परीक्षण

3500 किमी रेंज, 2 टन परमाणु बम ले जाने में है सक्षम

विशाखापत्तनम (एजेंसी)। भारत ने मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में अपनी परमाणु संचालित पनडुब्बी आईएनएस अरिघात से 3500 किलोमीटर रेंज वाली इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के-4 का परीक्षण किया। यह परीक्षण विशाखापत्तनम तट के पास किया गया। रक्षा मंत्रालय की ओर से इस परीक्षण पर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह ठोस ईंधन वाली के-4 मिसाइल थी, जो दो टन परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल भारत की परमाणु हथियार त्रयी के समुद्री हिस्से को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सूत्रों के हवाले से लिखा- मंगलवार के परीक्षण का व्यापक विश्लेषण किया जाएगा, ताकि यह तय हो सके कि क्या सभी निर्धारित तकनीकी पैरामीटर और मिशन उद्देश्य पूरे हुए हैं या कोई कमी रह गई है। बैलिस्टिक मिसाइलों, विशेष रूप से पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली मिसाइलों को पूर्ण ऑपरेशनल स्टेटस हासिल करने के लिए कई परीक्षणों की जरूरत पड़ती है। दो स्टेज वाली के-4 मिसाइल के पहले कई परीक्षण वर्षों से समुद्र के भीतर सबमर्सिबल पॉन्टून प्लेटफॉर्म से किए जाते रहे हैं। हालांकि नवंबर 2024 में इसे पहली बार आईएनएस अरिघात से दागा गया था। आईएनएस अरिघात भारत की दूसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी है, जो परमाणु हथियारों वाली बैलिस्टिक मिसाइलें (नौसेना की भाषा में एसएसबीएन) ले जाने में सक्षम है। इसे पिछले साल 29 अगस्त को कमीशन किया गया था। यह 6,000 टन वजनी पनडुब्बी त्रि-सेवा रणनीतिक बल कमांड द्वारा संचालित की जाती है। इसकी पूर्ववर्ती पनडुब्बी अरिहंत, जो 2018 में पूरी तरह ऑपरेशनल हुई, केवल 750 किलोमीटर रेंज वाली के-15 मिसाइलें ले जा सकती है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल कार्यक्रम के तहत होगी।

सेना के जवानों को सोशल मीडिया इस्तेमाल की इजाजत

इंस्टाग्राम पर कमेंट की मनाही, वॉट्सएप पर मैसेज कर सकेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय सेना के जवानों को पांच साल बाद सोशल मीडिया एप्स के इस्तेमाल की परमीशन मिल गई है। हालांकि कुछ शर्तें लागू रहेंगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, नई गाइडलाइन के तहत जवान इंस्टाग्राम पर रील, फोटो और वीडियो देख सकेंगे, लेकिन लाइक, कमेंट करने की अनुमति नहीं है। वॉट्सएप, टेलीग्राम जैसे एप्स पर गैर-गोपनीय जानकारी शेयर कर सकेंगे। इसके अलावा यूट्यूब और एक्स का इस्तेमाल केवल जानकारी के लिए किया जा सकेगा। वहीं, लिंक्डइन, स्काइप और सिग्नल एप के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। सरकार ने 2020 में संवेदनशील सूचनाएं लीक होने की आशंका के चलते जवानों और अधिकारियों को 89 एप हटाने का आदेश दिया था। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जूम और पबजी शामिल थे। इन एप के जरिए उस वक्त हनीट्रैप के कई मामले सामने आए थे। समय के साथ इंफॉर्मेशन की दुनिया बदल रही, सेना से जुड़ एक सूत्र ने बताया कि गाइडलाइंस में यह बदलाव कुछ दिन पहले किया गया था। जानकारी अब सामने आई है और यह भारतीय सेना के सभी रैंकों पर लागू होता है।

राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल ट्रस्ट से 3,811 करोड़ का चंदा

● भाजपा को 2024-25 में सबसे ज्यादा 3,112 करोड़; कांग्रेस को सिर्फ 299 करोड़ मिले

नई दिल्ली (एजेंसी)। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजनीतिक दलों को नौ इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए 3,811 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इसमें से ?3,112 करोड़ केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मिले। यह कुल फंड का करीब 82 फीसदी है। यह जानकारी इलेक्टोरल ट्रस्ट्स की ओर से चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट्स से सामने आई है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड इन रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाकी सभी दलों को मिलाकर करीब 400 करोड़ (10 फीसदी) फंड मिला। इसमें कांग्रेस को 299 करोड़ मिले, जो कुल चंदे का 8 फीसदी से भी कम है। इलेक्टोरल ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड संस्था होती है, जो कॉर्पोरेट कंपनियां और व्यक्तियों से चंदा लेकर राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचाती है। ट्रस्ट को चंदे की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है। इससे चंदे का रिकॉर्ड बना रहता है और पता चलता है कि किस पार्टी को कितना दान मिला। 20 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, चुनाव आयोग के पास 19 में से 13 इलेक्टोरल ट्रस्ट्स की रिपोर्ट मौजूद थी। इनमें से 9 ट्रस्ट्स ने 2024-25 में कुल 3,811 करोड़ चंदा दिया, जो 2023-24 के 1,218 करोड़ के मुकाबले 200 फीसदी से ज्यादा और तीन गुना है। भाजपा को चंदा देने के मामले में प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट सबसे आगे रहा।

बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या

7 दिन में दूसरी घटना, पहले दीपू को मारकर जलाया था

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश में एक बार फिर भीड़ ने हिंदू युवक को पीट-पीटकर मार डाला है। घटना बुधवार रात करीब 11.00 बजे राजबाड़ी जिले के होसेनडांगा गांव में हुई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान 29 वर्षीय अमृत मंडल उर्फ सम्राट के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि अमृत मंडल को भीड़ ने जबरन वसूली के आरोप में मार डाला। मृतक होसेनडांगा गांव का ही निवासी था।

पुलिस ने अमृत के साथी मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया है। उसके पास से दो हथियार बरामद किए। पुलिस ने बताया कि सम्राट के खिलाफ पांग्शा पुलिस स्टेशन में दो मामले दर्ज हैं। इनमें एक हत्या का मामला भी शामिल है। इससे पहले 18 दिसंबर को ढाका के पास हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने हत्या कर दी थी। बाद में उसे पेड़ पर लटकाकर जला दिया था। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों ने सम्राट पर एक आपराधिक गिरोह बनाने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक वह लंबे समय से जबरन वसूली और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। भारत में लंबे समय तक छिपने के बाद वह हाल ही में घर लौटा था। कथित तौर पर सम्राट ने गांव के निवासी शाहिदुल इस्लाम से जबरन वसूली की रकम मांगी थी। 24 दिसंबर की रात सम्राट और उसके साथी शाहिदुल के घर पैसे लेने गए थे। जब घरवालों ने चोर-चोर चिल्लाकर शोर मचाया तो स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और सम्राट की पिटाई कर दी।

ट्रेड वार्ता में भारत का अमेरिका को फाइनल ऑफर

टैरिफ 50 से घटाकर 15 फीसदी करो, रूसी तेल पर लगी पेनाल्टी भी खत्म हो

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने अमेरिका के सामने ट्रेड वार्ता में अपना आखिरी प्रस्ताव रख दिया है। भारत चाहता है कि उस पर लगाए गए कुल 50 फीसदी टैरिफ को घटाकर 15 फीसदी किया जाए और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25 फीसदी पेनाल्टी लगाई गई है, उसे पूरी तरह खत्म किया जाए। दोनों देशों के बीच चल रही इस वार्ता से नए साल में कोई ठोस फैसला निकलने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल का कहना है कि समझौते पर जल्द सहमति बन सकती है, हालांकि उन्होंने कोई तय समय सीमा नहीं बताई। इस हफ्ते भारत और अमेरिका की व्यापार टीमों के बीच दिल्ली में बैठक हुई। बातचीत दो मुद्दों पर हो रही है। पहला एक बड़े और स्थायी व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है।

3 नई एयरलाइंस को केंद्र सरकार की हरी झंडी

● शंख एयर, अलहिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को मिला एनओसी

एविएशन सेक्टर में मोनोपॉली तोड़ने की तैयारी में हैं मोदी सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने एविएशन सेक्टर में कॉम्पिटिशन बढ़ाने और बड़ी एयरलाइनों पर निर्भरता कम करने के लिए तीन नई एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) जारी किया है। इन एयरलाइंस के नाम शंख एयर, अलहिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस हैं। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है, जब हाल ही में इंडिगो के ऑपरेशन से जुड़ी दिक्कतें सामने आई थीं। इसके बाद सरकार को लगा कि भारतीय एविएशन सेक्टर में ज्यादा कंपनियों और विकल्पों की जरूरत है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारतीय आसमान में ज्यादा एयरलाइंस को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि नई एयरलाइंस के आने से यात्रियों को बेहतर सेवा और ज्यादा विकल्प मिलेंगे। एनओसी मिलने का मतलब है कि सरकार ने इन कंपनियों को एयरलाइंस शुरू करने की आगे की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। अब अगला कदम डीजीसीए से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके साथ ही इन्हें नेटवर्क से जुड़ी सारी तैयारियां करनी होंगी।

बड़ी कंपनियों पर निर्भरता कम करने के लिए फैसला

भारत का घरेलू एविएशन बाजार आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में शामिल है। सरकार का मानना है कि जितनी ज्यादा एयरलाइंस होंगी, उतनी ही ज्यादा उड़ानें और सीटें मिलेंगी। इससे देश के अलग-अलग हिस्सों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और टिकट के दाम भी प्रतिस्पर्धा के कारण काबू में रहेंगे। इसी सोच के साथ सरकार नए खिलाड़ियों को मौका दे रही है, ताकि विमानन बाजार सिर्फ एक या दो बड़ी कंपनियों पर निर्भर न रहे और यात्रियों को ज्यादा विकल्प मिल सकें।

खालिदा जिया के बेटे की 17 साल बाद बांग्लादेश वापसी

● एयरपोर्ट पर एक लाख लोग पहुंचे, 3 घंटे तक रोड शो किया ● शेख हसीना पर एक भी शब्द नहीं बोले, स्वागत समारोह हुआ

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद देश लौट आए हैं। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे। तब हसीना सरकार में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे थे। आज तारिक के स्वागत में उनकी पार्टी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे। ढाका

एयरपोर्ट से लेकर 300 फीट रोड तक रोड शो किया। इस 13 किलोमीटर के रास्ते को कवर करने में उन्हें 3 घंटे का समय लगा। तारिक ने 17 मिनट भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम देश में शांति कायम करेंगे और नया बांग्लादेश बनाएंगे। हालांकि उन्होंने शेख हसीना को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। खालिदा जिया के बीमार होने की वजह से माना जा रहा है कि रहमान अगले पीएम के दावेदार हो सकते हैं। बांग्लादेश की राजनीति दो नेताओं के इर्द-गिर्द घूमती रही है, जिसमें एक अवामी लीग की नेता शेख हसीना थी और दूसरी अवामी लीग की खालिदा जिया। 1980 के दशक में बांग्लादेश में सैन्य शासन था।

पश्चिम क्षेत्र में बनेगा आधुनिक संपवेल

इंदौर। शहर की बढ़ती जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा पश्चिम क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बिजलपुर के समीप फल बाग क्षेत्र में निमार्णाधीन संपवेल का निरीक्षण किया। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस संपवेल की जल संग्रहण क्षमता 3 करोड़ लीटर से अधिक होगी। यह संपवेल आगरा-मुंबई रोड के पास विकसित किया जा रहा है, जिससे पश्चिम क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में जल आपूर्ति बेहतर हो सकेगी। महापौर ने बताया कि अन्नपूर्णा, द्वारकापुरी, राजेंद्र नगर, प्रगति नगर जैसे क्षेत्रों में तकनीकी कारणों से पेयजल टंकियां पूरी तरह नहीं भर पाती थीं। इस संपवेल के माध्यम से लगभग 10 पेयजल टंकियों तक पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए कि कार्य गुणवत्ता के साथ तय समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। जलकार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा बबलू ने कहा कि भविष्य की जल मांग को देखते हुए यह परियोजना पश्चिम क्षेत्र के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगी।

महू के ग्राम भगोरा में जनसंवाद कार्यक्रम

इंदौर। थाना महू के अंतर्गत ग्राम भगोरा में 24 दिसंबर को जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भुटिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश कुमार द्विवेदी, थाना प्रभारी राहुल शर्मा महू उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने ग्राम की भौगोलिक, सामाजिक और सामान्य जानकारी प्राप्त की। ग्रामीणों ने अपनी निजी एवं सार्वजनिक समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने ग्रामीणों को समस्याओं के समाधान के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। जनसंवाद के दौरान सामने आई सभी समस्याओं के उचित निराकरण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

कोरियर कंपनी के कंटेनर से पार्सल चोरी

इंदौर। लसूड़िया थाना इलाके में मुंबई से आए कोरियर कंपनी के कंटेनर से अज्ञात बदमाशों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया। घटना 10 दिसंबर की सुबह लगभग 3.30 बजे हुई। डीटीडीसी कंपनी के ड्राइवर विकास कुमार मुंबई से देवास नाका इंदौर आए थे। उन्होंने एमएच-46 बीयू 8189 नंबर के कंटेनर को लोडिंग के बाद गोयल ग्रीन कॉलोनी के सामने खड़ा किया और शौचालय जाने के लिए चले गए। आधे घंटे बाद जब ड्राइवर वापस लौटा, तो उसने देखा कि कंटेनर के पीछे के गेट की सील टूटी हुई थी और कंटेनर में रखे 191 पार्सल गायब थे। इन पार्सलों की कुल कीमत 5,53,010 रुपए बताई जा रही है। घटना की सूचना तुरंत कंपनी के अधिकारियों और पुलिस को दी गई।

सड़क हादसे के बाद धमकियों का मामला

इंदौर। लसुड़िया थाना क्षेत्र की युवती सड़क हादसे के बाद मानसिक रूप से परेशान हो गई। अरण्य नगर निवासी कसक पिता मुकेश माणिक की एक्टिवा को वसीम खान नामक युवक ने बाइक से टक्कर मार दी थी। इस हादसे में युवती की एक्टिवा क्षतिग्रस्त हो गई थी। वसीम ने वाहन की मरम्मत के लिए 10 हजार रुपए का भुगतान किया और दोनों पक्षों ने आपसी समझौता कर लिया। युवती ने इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। लेकिन 8 दिसंबर को वसीम ने युवती के मोबाइल पर कॉल कर उसे निजी जानकारी देने के लिए दबाव डाला। युवती के इनकार करने पर उसने गालियां और जान से मारने की धमकियां देनी शुरू कर दीं। युवती ने पुलिस को बताया कि वसीम ने कहा कि उसके पास उसके फोटो हैं और उसने इंतजाम कर दिया है। लगातार धमकियों के कारण युवती मानसिक रूप से परेशान हो गई।

व्यक्ति ने पड़ोसियों की प्रताड़ना में आत्महत्या की

इंदौर। विजय नगर थाना क्षेत्र के कल्प कामधेनु नगर में व्यक्ति की आत्महत्या की घटना ने लोगों को सकते में डाल दिया। मृतक योगेश वर्मा पिता हुकुम चंद (42) ने 21 दिसंबर को अपने घर पर जहरीली वस्तु सेवन कर ली थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जांच में पता चला कि योगेश लंबे समय से अपने पड़ोसी नारायण साहू, उनकी पत्नी सुशीला और बेटे अपूर्व से परेशान थे। पड़ोसी पार्किंग विवाद और पुराने कानूनी मामले को लेकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। परिजनों के बयान और प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने पड़ोसी परिवार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने दो चाकूबाज युवकों को पकड़ा

इंदौर। कनाड़िया पुलिस ने असामाजिक तत्वों और अवैध हथियार रखने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना और संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर दो युवकों को अलग-अलग स्थानों से पकड़ा गया। पकड़े गए युवकों की पहचान रितिक पिता रितेश राव निवासी भूरी टेकरी और आदित्य पिता कैलाश पांचाल निवासी आईडीए मल्टी स्कीम नंबर 140 के रूप में हुई। उनके पास से चाकू बरामद हुए। दोनों के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर हथियार रखने और संभावित अपराध के लिए आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

एटीएम में तोड़फोड़ और चोरी की कोशिश

इंदौर। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में एटीएम में चोरी की कोशिश की घटना ने लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी। इंडिया वन कंपनी के एटीएम में अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ की और सुरक्षा उपकरणों, लॉक और की-पैड को क्षतिग्रस्त कर दिया। कंपनी अधिकारी अमित बाहेती ने बताया कि बदमाशों ने एटीएम के भीतर लगे कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रकरण दर्ज किया और आसपास लगे फुटेज की जांच शुरू कर दी।

एक ही दिन में साइबर फ्रॉड के आधा दर्जन मामले, रिटायर्ड मैनेजर, व्यापारी को ठगा

डिजिटल अरेस्ट, क्रेडिट कार्ड लिमिट, ऑनलाइन लॉटरी के नाम ठगी की गई

इंदौर। शहर के 6 अलग-अलग थानों में साइबर फ्रॉड के 6 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। इन मामलों में डिजिटल अरेस्ट, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने और ऑनलाइन लॉटरी के नाम पर की गई ठगी शामिल है। पुलिस सभी मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। यहां एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर 76 वर्षीय रवि कुमार कामरा को वीडियो कॉल के जरिए करीब छह घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। आरोपियों ने पीड़ित को यह कहकर डराया कि उसके खाते में 20 करोड़ रुपए का संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुआ है। इसके बाद लिंक भेजकर उसे अलग-अलग खातों में करीब 5 लाख रुपए जमा करवाए गए।

17 नवंबर 2025 को उन्हें व्हाट्सएप पर कॉल आया और पहले व्हाट्सएप चेक करने को कहा गया। इसमें कुछ तस्वीरें और दस्तावेज थे, जिनमें जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल की फोटो थी। बैंक अधिकारियों द्वारा परिवार को जानकारी देने पर डिजिटल अरेस्ट ठगी का खुलासा हुआ। इसके बाद साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई। व्यापारी शरद कुमार मिश्रा निवासी श्याम नगर की शिकायत पर हीरानगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। नवंबर 2025 में उनका टेलीग्राम के माध्यम से कुछ लोगों से संपर्क हुआ। उन्होंने शरद को एक अमेरिकी कंपनी के बारे में बताया। पहले 10 हजार रुपए निवेश करने पर 12 हजार रुपए का मुनाफा दिखाया गया। इसके बाद अलग-अलग चरणों में लाखों रुपए निवेश करवा लिए गए। इंटरनेट पर जांच करने पर फर्जीवाड़े का पता चला। इसके बाद 12 दिसंबर को साइबर ऑफिस रीगल में शिकायत की गई।

लॉटरी के नाम पर ठगी

कैलाश चंद्र मालवीय की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ रावजी बाजार थाने में एफआईआर दर्ज की गई। 29 नवंबर 2025 को उन्हें केरल ऑनलाइन सर्विस तिरुवनंतपुरम लॉटरी विभाग के नाम से कॉल आया और 1 लाख रुपए की लॉटरी लगने की बात कही गई। उनके एसबीआई अकाउंट से यूपीआई के जरिए 1 लाख 31 हजार रुपये के अनाधिकृत लेन-देन हो गए। जब ठग से संपर्क किया गया तो उसने 74 हजार रुपए और मांगे। फिर साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की।

इलाज के बहाने ठगी

मुकुंद सूबेदार निवासी धनवंतरी नगर की शिकायत पर राजेंद्र नगर पुलिस ने दो मोबाइल कस्टमरों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। उन्हें 23 नवंबर को उन्हें एक फोन आया। उसने परिचित बताया और बेटे के बॉम्बे अस्पताल में इलाज का बहाना बनाकर अलग-अलग खातों में छह बार में 1 लाख 57 हजार रुपये ट्रांसफर करवा लिए। उधर, बाणगंगा पुलिस ने उदय राज कश्यप की शिकायत पर 1 लाख 10 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज किया है। आरोपी मोबाइल कस्टमर ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर नवंबर 2025 में उनके अकाउंट से रुपए ट्रांसफर किए।

ठगी के कुछ और मामले

मल्हारगंज इलाके में फैक्ट्री संचालक मुरलीधर के साथ उनके यहां काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ठगी की। उनके फैक्ट्री अकाउंट से करीब 11 लाख 54 हजार रुपए कपिल टांक के खाते में ट्रांसफर किए गए। उनकी शिकायत पर हिमांशु पिता तेज कुमार जोशी निवासी द्वारकापुरी, सुदामा नगर और उसके साथी कपिल कुमार टांक निवासी कोमल रेसिडेंसी, गोपुर चौराहा के खिलाफ ऑनलाइन धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। एडीशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि सभी मामलों में जांच जारी है। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी अनजान कॉल, लिंक या लालच में आकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

एएसआई को 5 साल के लिए कांस्टेबल बनाया, अनुशासन तोड़ने की सजा दी

विभाग सुधार के तहत 'ऑपरेशन क्लीन' में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

इंदौर। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ 'ऑपरेशन क्लीन' के अंतर्गत लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत न केवल बाहरी व्यवस्था, बल्कि विभाग के अंदर की कार्यप्रणाली को भी दुरुस्त किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को एक और पुलिसकर्मी पर गंभीर कार्रवाई की गई। थाना तिलक नगर की एफआरवी (फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल) में पदस्थ एएसआई रामेश्वर परमार को पांच वर्ष के लिए पदावनत करते हुए प्रधान आरक्षक बना दिया गया। सूत्रों के अनुसार ड्यूटी के दौरान एएसआई अत्यधिक शराब के नशे में सोते हुए पाए गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने साथ तैनात कर्मचारियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंची। बताया जा रहा है कि एएसआई रामेश्वर परमार शराब पीने और लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने के आदी रहे हैं। अपने सेवाकाल के दौरान वे पहले भी इसी तरह की अनुशासनहीनता के चलते दंडित किए जा चुके हैं। बार-बार चेतावनी और सजा के बावजूद सुधार नहीं होने पर विभाग ने कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें पदावनत करने का निर्णय लिया है। इस कार्रवाई के बाद अब रामेश्वर परमार वर्ष 2029 में सेवानिवृत्ति तक प्रधान आरक्षक के पद पर ही रहेंगे। पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि अनुशासनहीनता, शराब सेवन और ड्यूटी में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में आगे भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।

पचमढ़ी सबसे ठंडा फिर नौगांव, भोपाल में 9.8 और इंदौर में पारा 8 डिग्री पर

उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवा के कारण रात का तापमान गिरा

इंदौर। ठंड और कोहरे का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। पचमढ़ी में इस मौसम में पहली बार न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच गया। मंगलवार रात यहां पारा गिरकर 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। आने वाले दिनों में ठंड और तेज हो सकती है, जिससे लोगों के न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर असर पड़ने की आशंका है।

न्यूनतम तापमान के मामले में नौगांव (छतरपुर) प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा शहर रहा, जहां रात का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा राजगढ़ में 7.4, मलाजखंड में 7.6, रीवा में 8.2 और उमरिया में 8.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। बुधवार सुबह कुछ शहरों में कोहरे से राहत जरूर मिली, लेकिन इंदौर, खजुराहो, रीवा, सतना, दतिया, गुना, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, मंडला, नरसिंहपुर और नौगांव में घने कोहरे का असर साफ दिखाई दिया। कई जगह विजिबिलिटी 2 से 4 किलोमीटर तक सीमित रही। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं और साफ आसमान के कारण रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है। ऐसे में लोगों को ठंड से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगले 2 दिन तक कोहरे का असर तो कम रहेगा, लेकिन ठंड का असर बढ़ जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार, न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। अगले 5 दिन तक मौसम साफ रहेगा और कहीं भी बारिश होने के आसार नहीं हैं। जिस तरह मानसून के चार महीने (जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर) में से दो महीने जुलाई-अगस्त महत्वपूर्ण रहते हैं और इन्हीं में 60 प्रतिशत या इससे अधिक बारिश हो जाती है, ठीक उसी तरह दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इन्हीं दो महीने में प्रदेश में उत्तर भारत से सर्द हवाएं ज्यादा आती हैं।

नए साल की रात इंदौर में पुलिस का सुरक्षा महाजाल दिखेगा

हुड़दंग, नशा खोरी और नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई

इंदौर। नए साल के जश्न को लेकर इंदौर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। 31 दिसंबर की रात शहरभर में सुरक्षा का महा-जाल बिछाया जाएगा। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए इस बार कोई रियायत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हर थाना स्तर पर पुलिस स्टाफ आयोजकों से समन्वय कर रहा है और केवल उन्हीं आयोजनों को अनुमति दी जाएगी, जो तय कानून के सभी प्रावधानों का पालन करेंगे। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि डीजे और साउंड सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश सख्ती से लागू रहेंगे तथा तय समय-सीमा का पालन अनिवार्य होगा।

नियमों के उल्लंघन पर आयोजकों के साथ-साथ कार्यक्रम में शामिल लोगों पर भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो प्रमुख आयोजनों और सार्वजनिक स्थलों पर तैनात रहेंगी। वहीं ट्रैफिक पुलिस फॉगिंग, रूट प्लानिंग और पार्किंग व्यवस्था तक खुद मॉनिटर करेगी। एसीपी, डीसीपी सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी और विशेष यूनिट्स पूरी रात मैदान में सक्रिय रहेंगे। पुलिस कमिश्नर ने दो-टूक कहा कि नशे में हुड़दंग, अवैध गतिविधि या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने की कोशिश करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने युवाओं से अपील की कि जश्न जरूर मनाएं, लेकिन जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ। पुलिस की मौजूदगी हर जगह रहेगी। इंदौर पुलिस की तैयारियों से साफ है कि इस बार नए साल की रात धूम तो होगी, लेकिन कानून की सीमा पार करने वालों के लिए यह रात भारी पड़ सकती है।

3.72 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को रोका, सतर्कता से बची कंपनी

जेपी मॉर्गन बैंक ने खाते में जमा रकम को होल्ड कर दिया गया

इंदौर। अंतर्राष्ट्रीय ठगी की कोशिश को इंदौर साइबर सेल ने नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई में इंदौर की निजी कंपनी की 3.72 करोड़ रुपए की राशि को फ्रीज कराया, उन्हें पूरी राशि वापस भी दिलाई गई। यह संभव इसलिए हुआ कि समय रहते पुलिस ने 'इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर' जरिए कार्रवाई की और बैंक ने उस राशि की फ्रीज कर दिया।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इंदौर स्थित शिवगंगा ड्रीलर्स प्राइवेट लिमिटेड को अमेरिका की कंपनी को भुगतान करना था। इसका फायदा साइबर अपराधियों ने कंपनी को बिल्कुल असली दिखने वाले फर्जी ईमेल भेजे। इसके जरिए ठगों ने कंपनी से अमेरिका के संदिग्ध बैंक खाते में भुगतान करवा लिया। इसके बाद ठगों ने फिर से मेल भेजकर कहा कि भुगतान रद्द हो गया है, नए खाते में दोबारा पैसा भेजने को कहा। इस बीच कंपनी को शक हुआ और उन्होंने अपने असली वेंडर से फोन पर बात की, तब ठगी का खुलासा हुआ। कंपनी ने तुरंत स्टेट साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। टीआई दिनेश वर्मा ने बताया कि स्टेट साइबर सेल इंदौर द्वारा भारतीय साइबर पोर्टल पर शिवगंगा डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड ने शिकायत की थी। जिसमें बताया कि अमेरिका के हॉउसटन स्थित उसकी कंपनी के वेंडर, इनोवेक्स इंटरनेशनल इंक को 415,017.58 डॉलर इंडियन करेंसी में लगभग 3.72 करोड़ रुपए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के माध्यम से व्यापारिक भुगतान किया जाना था। इसमें साइबर अपराधियों ने बिजनेस ईमेल कंप्रोमाइज (बीईसी) तथा स्पूफिंग ईमेल का उपयोग कर करोड़ों रुपए अंतरराष्ट्रीय फॉरेन रेमिटेंस, अमेरिका की जेपी मॉर्गन बैंक के एक संदिग्ध एकाउंट में धोखाधड़ी से ट्रांसफर करवा ली। मामला अमेरिका से जुड़ा होने के कारण भारत और अमेरिका के 'इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर' पोर्टल पर भी शिकायत की गई। पुलिस के समय पर सूचना देने से जेपी मॉर्गन बैंक ने खाते में जमा रकम को होल्ड कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रक्रिया के बाद बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से पूरी राशि कंपनी को वापस मिल गई।

उपभोक्ता जागरूकता, त्वरित निवारण, मिलावट के विरुद्ध प्रशासन प्रतिबद्ध

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के तहत उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम

इंदौर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस-2025 के अवसर पर इंदौर में विविध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिले का मुख्य कार्यक्रम कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर शिवम वर्मा की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग क्रमांक 1 एवं 2 के अध्यक्ष विकास राय मुख्य अतिथि थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में आयोग क्रमांक 1 के सदस्य कुंदन सिंह चौहान, डॉ निधि बारंगे और आयोग क्रमांक 2 के सदस्य लालजी तिवारी उपस्थित शामिल हुए। कलेक्टर ने कहा कि उपभोक्ताओं को शुद्ध, गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री सही दाम और सही माप के अनुसार उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। मिलावटखोरों के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी सहित सभी सेवाओं में समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता जागरूकता, त्वरित निवारण और मिलावट के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस इंदौर प्रशासन की निरंतर प्रतिबद्धता है। स्वागत भाषण जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने दिया। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता मार्गदर्शन केन्द्र के माध्यम से पिछले एक वर्ष में 300 से अधिक प्रकरणों का सफल निराकरण किया गया। विभागीय नवाचारों की कुंदन सिंह चौहान तथा डॉ. निधि बारंगे ने सराहना की। मेडिकल क्षेत्र में उपभोक्ता जागरूकता पर भी बल दिया गया। मुख्य अतिथि विकास राय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रभावी प्रावधानों को उदाहरणों सहित समझाया। सुप्रीम कोर्ट में प्रचलित ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी गाइडलाइंस/दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। प्रश्नोत्तरी सत्र में उपस्थित उपभोक्ताओं के प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए। साथ ही, आयोगों द्वारा पिछले दो वर्षों में समय-सीमा में पारित आदेशों एवं उनके क्रियान्वयन की प्रगति से अवगत कराया गया।

कार्यक्रम के प्रारंभ में कलेक्टर एवं अन्य अतिथियों ने विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नापतौल विभाग, राज्य सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, बीएसएनएल, विद्युत विभाग, सांची दुग्ध संघ, कृषि विभाग सहित स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों द्वारा उपभोक्ता अधिकारों एवं कानूनी जानकारी का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने उपभोक्ता जागरूकता के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए डीजी मिश्र, मुकेश अमोलिया, आरके शुक्ला सहित विभिन्न संगठनों/अधिकारियों को प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।

उपभोक्ता मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना में उल्लेखनीय योगदान के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राहुल शर्मा का विशेष सम्मान किया गया। तीन श्रेष्ठ जागरूक उपभोक्ताओं रामनरेश भदौरिया, प्राची आर्य एवं राशि कौशिक को तुलसी का पौधा एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आभार सहायक आपूर्ति अधिकारी एसएस व्यास ने व्यक्त किया तथा संचालन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एसएस गामड द्वारा किया गया।

संपादकीय

परमाणु ऊर्जा बिल पर सवाल

मोदी सरकार ने देश में परमाणु ऊर्जा बिल जिस तेजी से पास कराया और इसे कानून के रूप में लागू भी कर दिया गया, उससे कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल मुख्यतः इस कानून की पारदर्शिता, सुरक्षा और सरकार की राजनीतिक मंशा को लेकर है। हालांकि सरकार ने सभी आशंकाओं को खारिज किया है। 'शांति विधेयक' दरअसल, संसद से पास हुए उस बिल का नाम है जिसके ज़रिए निजी क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश की इजाज़त दी गयी है। गौरतलब है कि विगत 17 दिसंबर को लोकसभा में विपक्ष के वाकआउट के बीच 'शांति विधेयक' पास हो गया। दो दिन बाद ही राष्ट्रपति ने भी इस पर मुहर लगा दी। यहां शांति से तात्पर्य Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill, 2025 (नाभिकीय ऊर्जा का सतत दोहन एवं उन्नयन विधेयक 2025) से है। नया क़ानून परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 का स्थान लेगा, जिसका अमेरिकी परमाणु आपूर्तिकर्ता लंबे समय से वहाँ की सरकार के समर्थन से विरोध करते रहे हैं। इस नए और पुराने क़ानून फर्क यह है कि पुराने कानून के तहत सिर्फ सरकारी कंपनी NPCIL ही प्लांट बना और चला सकती थी। SHANTI के तहत भारतीय निजी कंपनियाँ जॉइंट वेंचर में न्यूक्लियर प्लांट बना और चला सकती हैं। इसमें 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफ़डीआई की अनुमति होगी। इसका उद्देश्य 2047 तक 100 GW (गीगावॉट) परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना है। भारत में कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी सिर्फ़ 3% है। ज़ाहिर है, सरकार इसे एक बड़ा कदम मान रही है। लेकिन विपक्ष ख़ासतौर पर कांग्रेस की कुछ आपत्तियां हैं। पहली है आपूर्तिकर्ताओं को मुआवज़ा देने से छूट। शांति क़ानून पहले की वह क़ानूनी बाध्यता को ख़त्म करता है जिसके तहत दुर्घटना होने पर आपूर्तिकर्ता को ज़िम्मेदार मानते हुए मुआवज़ा वसूला जाता था। इस क़ानून के तहत ख़राब डिज़ाइन, घटिया पुर्ज़ों या लापरवाही की ज़िम्मेदारी से कॉरपोरेट बरी रहेगा। दुर्घटना से हुए नुक़सान की भरपाई भारतीय टैक्सपेयर करेंगे। यह कानून ऐसे वक्त पर आया है, जब अमेरिका के साथ व्यापार संधि के लिए भारत की बातचीत चल रही है। तो क्या इस कानून को लाने के पीछे अमेरिकी दबाव था? क्योंकि यह क़ानून अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर के रियेक्टर बेचने में मदद करेगा। बताया जा रहा है कि अडानी इस कानून के तहत 1.6 गीगावाट का न्यूक्लियर पॉवर प्लांट यूपी में लगाने जा रहे है। यह प्लांट पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा। जहां NPCIL ऑपरेशन संभालेगी, लेकिन अडानी की कंपनी निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतज़ाम करेगी। साफ है कि सरकार अब परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र भी निजी क्षेत्र के लिए खोल रही है। इस संदर्भ में विपक्ष के विरोध को खानापूर्ति नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कुछ सवालों के जवाब अभी मिलने हैं। मसलन सेफ्टी का खतरा। यानी पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए तो चेरनोबिल-फुकुशिमा जैसी दुर्घटना का डर है। कानून में दुर्घटनाओं को लेकर आपूर्तिकर्ताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा। दुर्घटना के पीड़ितों को कम मुआवजा मिलेगा। सबसे बड़ी बात पारदर्शिता की कमी है। क्योंकि सरकार ने यह पहले ही तय कर दिया है कि 'प्रतिबंधित' क्षेत्रों को आरटीआई से बाहर रखा जायेगा। यही वजह है कि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की ट्रेड यूनियंस और इंजीनियर्स भी इसका विरोध कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जब यूपीए 1 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने परमाणु ऊर्जा समझौता किया था, तब बीजेपी ने उसका पुरजोर विरोध करते हुए इसे भारत की संप्रभुता पर हमला बताया था। अब वही बीजेपी इस कानून की पुरजोर वकालत कर रही है।

बांग्लादेश: अल्पसंख्यकों की पीड़ा व लोकतंत्र की परीक्षा

नजरिया

अंशुमान
लेखक संसद टीवी से सम्बद्ध पत्रकार हैं।

आज, पाँच दशक बाद, उसी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर हिंदू, बौद्ध और ईसाई की स्थिति पर उठते प्रश्न हमें फिर से आत्ममंथन के लिए विवश करते हैं। यह विषय केवल डिप्लोमैसी का नहीं है, न हीं इसे किसी एक देश के आंतरिक मामले के रूप में सीमित किया जा सकता है। यह प्रश्न मानवाधिकारों का है, लोकतंत्र की आत्मा का है और उस नैतिक जिम्मेदारी का है जो हर सभ्य समाज पर लागू होती है। जब हम अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अक्सर यह एक सांख्यिकीय शब्द बनकर रह जाता है। लेकिन वास्तविकता में अल्पसंख्यक कोई अमूर्त अवधारणा नहीं हैं। वे किसान हैं जिनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया गया, वे महिलाएं हैं जो असुरक्षा और भय में जीवन जीने को मजबूर हैं, वे बच्चे हैं जो अपने धर्म और पहचान के कारण स्कूल में अपमान और हिंसा का सामना करते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएँ कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इनकी आवृत्ति और तीव्रता ने चिंता को गहरा किया है। मंदिरों पर हमले, धार्मिक प्रतीकों की तोड़फोड़, झूठे मुकदमों के ज़रिये उत्पीड़न, सामाजिक बहिष्कार और जबरन पलायन—ये सभी घटनाएँ एक ऐसे माहौल की ओर संकेत करती हैं जहाँ भय धीरे-धीरे सामान्य जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है।

दक्षिण एशिया का इतिहास केवल सीमाओं का इतिहास नहीं है, यह साझा स्मृतियों, साझा संघर्षों और साझा संवेदनाओं का इतिहास है। भारत और बांग्लादेश का संबंध भी ऐसा ही है एक ऐसा रिश्ता जो भाषा, संस्कृति, बलिदान और विश्वास से बना है। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान भारत ने न केवल एक पड़ोसी के रूप में, बल्कि एक संवेदनशील मानव समाज के प्रतिनिधि के रूप में अपना कर्तव्य निभाया। उस समय भारत ने शरणार्थियों को आश्रय दिया, अंतरराष्ट्रीय दबाव सहा और अंततः एक नए राष्ट्र के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई।

आज, पाँच दशक बाद, उसी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर हिंदू, बौद्ध और ईसाई की स्थिति पर उठते प्रश्न हमें फिर से आत्ममंथन के लिए विवश करते हैं। यह विषय केवल डिप्लोमैसी का नहीं है, न ही इसे किसी एक देश के आंतरिक मामले के रूप में सीमित किया जा सकता है। यह प्रश्न मानवाधिकारों का है, लोकतंत्र की आत्मा का है और उस नैतिक जिम्मेदारी का है जो हर सभ्य समाज पर लागू होती है। जब हम अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अक्सर यह एक सांख्यिकीय शब्द बनकर रह जाता है। लेकिन वास्तविकता में अल्पसंख्यक कोई अमूर्त अवधारणा नहीं हैं। वे किसान हैं जिनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया गया, वे महिलाएं हैं जो असुरक्षा और भय में जीवन जीने को मजबूर हैं, वे बच्चे हैं जो अपने धर्म और पहचान के कारण स्कूल में अपमान और हिंसा का सामना करते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएँ कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन हाल के वर्षों में इनकी आवृत्ति और तीव्रता ने चिंता को गहरा किया है। मंदिरों पर हमले, धार्मिक प्रतीकों की तोड़फोड़, झूठे मुकदमों के ज़रिये उत्पीड़न, सामाजिक बहिष्कार और जबरन पलायन—ये सभी घटनाएँ एक ऐसे माहौल की ओर संकेत करती हैं जहाँ भय धीरे-धीरे सामान्य जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है।

इसी संदर्भ में एक बेहद धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी दर्दनाक घटना ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचा है। 18 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले में 25-27 साल के हिंदू युवक, दीपू चंद्र दास, को भीड़ ने कथित ईशनिंदा आरोप में बेरहमी से पीटा और मार डाला। उसके बाद, उसकी लाश को एक पेड़ से बाँधकर आग लगा दी गई, यह न केवल एक हत्या थी, बल्कि एक ऐसा क्रूर कृत्य था जिसने लोगों को सकते में डाल दिया। इस घटना ने न केवल स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय में भय और खौफ पैदा किया है, बल्कि भारत सहित कई देशों में भी चिंता और विरोध की लहरें उठाई हैं। यह घटना यह दिखाती है कि जहाँ कानून का शासन कमजोर पड़ता है, वहाँ भीड़ की हिंसा ही न्याय का रूप ले लेती है और पीड़ितों की आवाज़ दब जाती है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस लिंचिंग की निंदा की है और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आश्वासन दिया है, लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति यह दर्शाती है कि संवेदी सेवाओं, प्रशासनिक संरक्षण, और सामाजिक सहभागिता की आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है।

असल में बांग्लादेश का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात तो करता है जो कि सराहनीय है और आदर्श भी है, लेकिन किसी भी संविधान की आत्मा उसकी किताबों में नहीं, बल्कि समाज के व्यवहार में बसती है। अमूमन देखा जाता है कि जब किसी देश में अल्पसंख्यकों को बार-बार अपनी सुरक्षा, अपनी आस्था और अपनी पहचान के लिए संघर्ष करना पड़े, तो यह उस व्यवस्था की विफलता का संकेत होता है। इसी के साथ एक यह भी सत्य है कि बांग्लादेश की आम जनता का एक बड़ा हिस्सा शांति और सह-अस्तित्व में विश्वास करता है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब कट्टर तत्वों को राजनीतिक संरक्षण, सामाजिक मौन और प्रशासनिक उदासीनता मिल जाती है। तब हिंसा केवल अपराध नहीं रह जाती, वह एक संदेश बन जाती है और वह संदेश होता ह, डर का संदेश।

कूटनीतिक और नैतिक दोनो रूपों में जब जब भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, तो इसे अक्सर हस्तक्षेप के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। बांग्लादेश का यह दृष्टिकोण न केवल संकीर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और मानवीय सच्चाइयों की अनदेखी भी करता है। भारत की चिंता तीन स्तरों पर समझी जानी चाहिए। पहला स्तर है मानवीय क्योंकि भारत स्वयं विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक धर्म, भाषाएँ और संस्कृतियाँ एक साथ जीवित हैं और सद्भभाव से रह रहे हैं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का आधार है। इसलिए जब कहीं भी धार्मिक उत्पीड़न होता है, तो भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है। भारत की चिंता का दूसरा स्तर है ऐतिहासिक क्योंकि भारत और बांग्लादेश का अतीत साझा रहा है। बांग्लादेश के कई अल्पसंख्यक परिवारों की जड़ें भारत से जुड़ी हैं उनके साथ हो रहा अन्याय भारत की सामाजिक स्मृति को भी आहत करता है। तीसरी चिंता का स्तर है क्षेत्रीय स्थिरता का स्तर क्योंकि जब किसी देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित होते हैं, तो उसका असर केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता है बल्कि पलायन, शरणार्थी संकट और सामाजिक असंतुलन पूरे क्षेत्र की शांति को प्रभावित करते हैं।

अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का सबसे दर्दनाक परिणाम होता है मौन पलायन। लोग रातों-रात अपने घर छोड़ देते हैं, अपनी जमीन, अपनी स्मृतियाँ, अपनी पहचान पीछे छोड़कर। यह पलायन न तो सरकारी आंकड़ों में पूरी तरह दर्ज होता है और न ही अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बनता है, लेकिन यह एक गहरी मानवीय त्रासदी है। भारत ने अतीत में ऐसे पलायन की कीमत चुकाई है। सीमावर्ती राज्यों पर इसका सामाजिक और आर्थिक दबाव पड़ता है। ऐसे में यह कहना कि यह भारत की समस्या है यह बिल्कुल वास्तविकता को उलट देने जैसा है। मूल समस्या वहाँ है जहाँ भय पैदा किया जा रहा है, जहां नागरिकों को दूसरे दर्जे का महसूस कराया जा रहा है।

किसी भी लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनावों में नहीं, बल्कि इस बात में होती है कि वह अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। बहुसंख्यक होना शक्ति का पैमाना हो सकता है, लेकिन जम्हूरियत की खूबसूरती उसी शक्ति पर संयमित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बांग्लादेश ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन यह विकास तब अधूरा रह जाता है जब वह भय और असमानता की नींव पर खड़ा हो। सच्चे विकास की परिभाषा वही है जिसमें हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, बिना अपनी आस्था छिपाए, बिना अपनी पहचान बदलने के दबाव के। कूटनीतिक तौर पर भारत ने कभी भी इस मुद्दे पर टकराव का रास्ता नहीं चुना बल्कि इन मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट रहा है संवाद, सहयोग और आपसी सम्मान। भारत यह मानता है कि बांग्लादेश की सरकार और समाज में इतनी क्षमता है कि वे इस समस्या का समाधान कर सकें। लेकिन संवाद तभी सार्थक होता है जब सच्चाई को स्वीकार किया जाए। समस्याओं से इनकार करना या उन्हें अतिश्योक्ति कहकर खारिज करना पीड़ितों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है।

बांग्लादेश सरकार बाखूबी जानती है कि इस समस्या का समाधान केवल कानून से नहीं, बल्कि सामाजिक इच्छाशक्ति से निकलेगा। बांग्लादेश में शिक्षा, मीडिया, धार्मिक नेतृत्व और राजनीतिक दलों सभी को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। नफरत के खिलाफ स्पष्ट संदेश, हिंसा के खिलाफ त्वरित न्याय और पीड़ितों के पुनर्वास के बिना भरोसा कभी बहाल नहीं हो सकता। भारत इस राह में सहयोगी बन सकता है अनुभव साझा करके, संवाद के मंच उपलब्ध कराकर और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काम करके। लेकिन पहला कदम वहीं से उठेगा जहाँ समस्या मौजूद है। अंततः यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारत का पक्ष किसी के खिलाफ नहीं है। भारत का पक्ष मानवता के साथ है। जब भारत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात करता है, तो वह सीमाओं से ऊपर उठकर एक सभ्य समाज की आवाज़ बनता है।

भारत की पड़ोसी होने के नाते चिंता स्वाभाविक है, और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते बोलना आवश्यक। चुप्पी अक्सर उत्पीड़क का साथ देती है, पीड़ित का नहीं। दक्षिण एशिया का भविष्य शांति, सह-अस्तित्व और विश्वास पर टिका है। यह तभी संभव है जब हर देश अपने घर में सबसे कमजोर नागरिक की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। अल्पसंख्यकों की पीड़ा को अनदेखा करके कोई भी राष्ट्र वास्तव में मजबूत नहीं बन सकता। भारत की अपेक्षा भी यही है और कामना भी कि बांग्लादेश अपने मूल आदर्शों की ओर लौटे, जहाँ धर्म नहीं, बल्कि इंसान की पहचान सबसे पहले हो।

लोकतंत्र के चार स्तंभों पर पुनर्विचार का समय

विचार

वीरेंद्र कुमार पालीवाल
सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारी

भारत का लोकतंत्र विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था मानी जाती है, जिसकी नींव 'जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन' के आदर्श पर टिकी है। किंतु स्वतंत्रता के सात दशक बाद, इसकी व्यावहारिक अभिव्यक्ति पर गहन मंथन का क्षण आ गया है। आज सबसे मूलभूत प्रश्न यह उभर रहा है- यदि शासन वास्तव में जनता का है, तो फिर 'शासक' और 'नौकर' की पारंपरिक अवधारणाएँ किस आधार पर खड़ी हैं ? क्या लोकतंत्र की संरचना के बारे में हमारी समझ अपर्याप्त या अधूरी तो नहीं रह गई है ? यह आज चिंतन का अहम विषय होना चाहिये ।

मूलभूत प्रश्न यह है कि 'मालिक' कौन है? और 'नौकर' कौन है ? यथाशीघ्र इसका भ्रम दूर किए जाने की आवश्यकता है।

लोकतंत्र में कार्यपालिका का प्राथमिक दायित्व है कि वह विधायिका द्वारा निर्मित जनहितकारी कानूनों एवं नीतियों को निष्पक्ष, समयबद्ध और भ्रष्टाचार-मुक्त ढंग से लागू करने में प्रभावी रूप से काम करे । इसका उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जहाँ प्रत्येक नागरिक स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और गौरवान्वित अनुभव करे। परंतु वास्तविकता अक्सर इस आदर्श से भिन्न दिखाई देती है। क्या कार्यपालिका, जिसे 'सेवक' की भूमिका निभानी चाहिए, व्यवहार में 'स्वामी' बन बैठी है ? और क्या जनता, जो वास्तविक 'मालिक' है, भ्रमित होकर अपनी इस हैसियत को भूल गई है ? बस यह विसंगति ही हमारे लोकतांत्रिक ढाँचे की सबसे गहरी चुनौती बनकर उभरी है।

'स्तंभ' की अवधारणा: एक अपूर्ण रूपक- विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया - इन चारों को लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता रहा है। 'स्तंभ' शब्द स्थिरता, दृढ़ता और अपरिवर्तनीय आधार का बोध कराता है। किंतु क्या यह रूपक आज के गतिशील लोकतंत्र के लिए पर्याप्त है ? नहीं कदापि नहीं , आज के दौर में यह अवधारणा किसी भी दृष्टि से सत्य प्रतीत नहीं होती ।

विधायिका एवं कार्यपालिका मूलतः गतिशील संस्थाएँ हैं। इनका कर्तव्य जनता के द्वार तक पहुँचना, उनकी आवश्यकताओं को समझना और सेवाओं को उनके घर तक पहुँचाना है। ये लोकतंत्र रूपी रथ के 'पहिए' हैं, जो निरंतर गति में रहकर ही उसे गंतव्य तक ले जा सकते हैं।

न्यायपालिका, जो नागरिक का अंतिम आश्रय-स्थल है, भी पूर्णतः स्वायत्त एवं स्थिर नहीं है। उसे अपने निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए अंततः कार्यपालिका तंत्र पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कई बार माननीय उच्चतम न्यायालय इस विषय पर गंभीरता पूर्वक अपनी बेबसी भी अभिव्यक्त कर चुका है । हकीकत में जनता ही वह वास्तविक एवं दृढ़ 'स्तंभ' है, जो इस पूरी व्यवस्था का आधार और अंतिम लक्ष्य दोनों है, और इस सार्वभौमिक सत्य को हम सभी को खुले तौर स्वीकार करना चाहिए ।

इस प्रकार, लोकतंत्र की छवि कुछ स्थिर स्तंभों और कुछ गतिशील पहियों की मिली-जुली संरचना की बनती है, जहाँ भूमिकाओं का स्पष्ट विभाजन धुंधला पड़ गया प्रतीत हो रहा है।

मीडिया: लोकतंत्र का गतिशील सेतु- इस संपूर्ण ढाँचे में मीडिया की भूमिका हमेशा से बिल्कुल ही अद्वितीय, महत्वपूर्ण, निर्णायक और सराहनीय रही है। शक्ति या संसाधनों से संपन्न न होते हुए भी, यह लोकतंत्र का सबसे तेजगामी पहिया है जो अपनी ख़ाली पड़ी थाली की जगह नागरिकों के भूखे पेट की चिंता करता है । यह कैरम-बोर्ड के स्ट्राइकर के समान ही, सूचना एवं विचारों को समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक उनकी मंज़िल तक पहुँचाता है। यह सत्ता की नीतियों को जनता तक और जनता की आकांक्षाओं एवं पीड़ाओं को सत्ता तक ले जाता है, अक्सर औपचारिक संवाद प्रक्रिया से भी पहले। इसीलिए मीडिया पर निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और राष्ट्रहित के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का दायित्व सर्वाधिक रूप से अलिखित परंतु स्वतः स्थापित हो गया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि मीडिया अपनी इस पवित्र जिम्मेदारी को पूरे आत्मविश्वास के साथ नए सिरे से स्थापित करे और लोकतंत्र के जीवंत सेतु के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे इस बात को स्वीकार करते हुए कि जनता का संपूर्ण व्यवस्थाओं पर विश्वास बनाए रखने में लोकतंत्र का तीव्र रूप से गतिशील एक मात्र मजबूत पहिया हमारा प्यारा विश्वसनीय मीडिया ही सक्षम है ।

पुनर्परिभाषा की ओर- एक नए लोकतांत्रिक मॉडल का आह्वान- वर्तमान समय की चुनौतियाँ, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता का अभाव, जवाबदेही की कमी और संस्थागत असंतुलन हमें स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि लोकतंत्र की परंपरागत अवधारणा को पुनर्परिभाषित करने का समय आ गया है। मूल मंत्र यह होना चाहिए कि जब तक कार्यपालिका तंत्र को पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन के लिए प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, तब तक लोकतंत्र का आदर्श साकार नहीं हो सकेगा। आवश्यकता इस नए संतुलन की है, जहाँ प्रत्येक संस्था की भूमिका स्पष्ट हो, उसकी जवाबदेही तय हो, और जनता की गरिमा व अधिकार सर्वोपरि हों। लोकतंत्र को मजबूत करने का मार्ग इसके मूल ढाँचे में आवश्यक सुधार एवं संतुलन से ही गुजरेगा।

अंततः लोकतंत्र को केवल चार स्तंभों पर एक जगह टिकी व्यवस्था की जगह स्थिरता और गति के सामंजस्य के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है । निष्कर्षतः लोकतंत्र को केवल चार स्थिर स्तंभों वाली इमारत के रूप में देखना अपर्याप्त है। यह एकतो एक चार प्रहरियों वाली जीवंत प्रणाली है, जहाँ जनता आधार-स्तंभ है, न्यायपालिका का 'विधि एवं न्याय' मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, कार्यपालिका क्रियान्वयन की शक्ति है, और मीडिया गतिशील संवाद का माध्यम। नए युग की माँग है कि इन सभी तत्वों के बीच स्थिरता एवं गतिशीलता, अधिकार एवं दायित्व का एक नया, स्पष्ट और संतुलित समीकरण स्थापित किया जाए, तभी हमारा लोकतंत्र वास्तव में 'जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन' बन सकेगा और अपने सर्वोच्च आदर्शों को साकार कर पाएगा।

देखते-देखते आ ही जाता है नया वर्ष

अलविदा 2025

विवेक कुमार मिश्र
लेखक हिंदी के प्रोफेसर हैं।

दिसंबर की तरह रहें। दिसंबर का नाम आते ही बहुत सारी बातें नये सिरे से उभरने लगती है। पूरा वर्ष ही आंखों में घूमने लगता है कि पूरा एक वर्ष निकल गया देखते देखते दिसंबर आ गया और हां दिसंबर आ गया तो चला ही जायेगा बहुत कुछ सौंपकर। दिसंबर होने को तो वर्ष का अंतिम महीना है पर यह अंतिम महीना पूरे वर्ष को एक एक कर गिनने को कहता है... दिसंबर के साथ ही हम सब हिसाब लगाने लगते हैं कि क्या क्या हो गया क्या कुछ बाकी रह गया और जो कुछ नहीं हुआ उसे भी जल्दी-जल्दी देखना है। यह विचार करना है कि आखिर इतने सारे काम जो हो जाने चाहिए थे वे क्यों नहीं हुए। जो रह गये उन्हें पूरा भी हमें ही करना है और दिसंबर में ही करना है क्योंकि जो दिसंबर है वह यही कहता है कि दिसंबर में काम पूरा कर लों नहीं तो नया वर्ष नये ढ़ंग से नये एजेंडे को लेकर आ जायेगा। फिर तुम चाह कर भी दिसंबर को दिसंबर की तरह जी नहीं पाओगे। दिसंबर को दिसंबर की तरह जीने के लिए आप तभी आगे आ सकते हैं जब अपने आप में अपडेट हों। अपने कार्य को खुद से करने की आदत रखते हों और किसी के भरोसे न बैठें हों। दिसंबर कभी ये नहीं कहेगा कि तुम किसी और का काम करों या तुम्हारे कार्य के लिए कोई और है। दिसंबर तो सबके लिए दिसंबर ही है। हर आदमी दिसंबर को जीना चाहता है अपने कार्य को पूरा करना चाहता है पर यह सब संभव ही तब होगा जब कार्य को कार्य की तरह लेते हों। दिसंबर जगा देता है पूरे साल को अपने साथ देखने के लिए। समय के साथ चलना, समय को जीना और समय में होना अपने आप में होना होता है। दिसंबर हर कार्य को करने को कहता है, कुछ भी टालना नहीं है, दिसंबर में टाल-मटोल नहीं चलेगा। जो है वह सब आज और अभी करना है। जो कोई दिसंबर को जनवरी की तरह लेने की कोशिश करता है वह कुछ नहीं कर पाता क्योंकि दिसंबर के पाएं में केवल दिसंबर ही होता है जबकि जनवरी के पाएं में आने वाले सभी महीने होते हैं।

दिसंबर आखिरी महीना है जहां पर पूरे वर्ष का हिसाब लगाया जाता है कि यह कर लें तो वह कर लें। यह सब कुछ व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि आप दिसंबर की तरह रहते हैं कि जनवरी की तरह। यदि आप दिसंबर की तरह जीते हैं तो आप अपने सारे कार्य खुद करने में भरोसा रखने वाले होते हैं और एक समय विशेष में आप अपना कार्य कर भी लेते हैं क्योंकि दिसंबर कार्य कराना जानता है। वह बात नहीं करता बस अपने कार्य को पूरा करने को कहता रहता है कि दिसंबर को दिसंबर की तरह जीते हुए आप अपने लक्ष्य को पूरा करें। दिसंबर किसी से कुछ नहीं कहता पर सब दिसंबर को मन से जीते हैं कि दिसंबर है और एक दिन दिसंबर की तरह चला जायेगा फिर दिसंबर का सारा काम दिसंबर के ही खाते में किया जायेगा, एक नये वर्ष के संग साथ को लिए लिए। दिसंबर रुकता नही भागा हुआ चलता है। आप सोचते हैं कि अभी तो दिसंबर की शुरुआत हुई है और सारे कामकाज कर ही लेंगे। ऐसी भी क्या जल्दी पर दिसंबर को जल्दी पड़ी रहती है वह रुकता नहीं, न ही ठहरता और दिन भी छोटे होते हैं और काम तो किसी न किसी रूप में पूरे वर्ष के बाकी रहते हैं जो दिसंबर के ही खाते में आते हैं। जो कुछ नहीं किया वह निकल कर अगले वर्ष के हिस्से में चला जायेगा और दिसंबर है कि बस देखता ही रह जायेगा। पर दिसंबर तो दिसंबर की तरह तमाम दावों और दबाव के बीच पड़ा ही रहता है उसे न जल्दी रहती न हड़बड़ी उसे पता है कि वह गति करें या न करें ग्रह नक्षत्रों की चाल धकेल कर उसे अगले वर्ष में ले जायेगी। यदि आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी दिसंबर अपनी गति से अगले वर्ष में चला ही जायेगा। आप परेशान हैं तो इसमें दिसंबर का कोई रोल नहीं हैं। आप खुद से परेशान हैं तो परेशान होते रहिए। दिसंबर का अहसास बस दिसंबर की शुरुआत में ही बना रहता है फिर तो कुछ भी हो जाए पखवाड़ा बीता नहीं कि दिसंबर दिखता ही नहीं फिर तो हर आंख में एक नया ही वर्ष बसा होता है। नये को देखने की ऐसी लालसा होती है कि आदमी को जो सामने है वह दिखता ही नहीं। दिसंबर पड़ा ही रहता है और लोग-बाग नये सिरे से नये नये सपने नये नये रंग देखने लगते हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा अग्निबाण पब्लिकेशन, 121, देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साईं कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

सर्दियों के फायदे केवल उसी को जिसके पास कोट है

व्यंग्य

कुन्दन सिंह परिहार

ज्ञानी लोग सर्दियों के बहुत से लाभ बताते हैं। मसलन, सर्दियां सेहत बनाने के लिए बढ़िया मौसम है। बादाम घोंटिए, मेवा खाइए और वर्जिश कीजिए। कहते हैं इस मौसम में हाज़मा बढ़िया काम करता है। जो खाइए सो भस्म।

लेकिन सवाल यह है कि जब महंगाई के मारे आदमी खुद ही भस्म हो रहा हो तो वह क्या खाए और क्या भस्म करे? आज के ज़माने में दो वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए। बादाम-मेवा अब दूध-घी की तरह देवताओं के भोजन हो गये हैं। देवताओं से मेरा मतलब उन नर-रत्नों से है जिनके पास माल की कमी नहीं है और जिन्हें महंगाई की गर्मी बिल्कुल नहीं व्यापती। ऐसे लोगों की हमारे देश में कमी नहीं है। लेकिन मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर पलने वाले परिवार में मूंगफली तो आ सकती है, बादाम ख्वाब की बात है।

बादाम और काजू-किशमिश बड़े लोगों की पार्टियों की शोभा बनते हैं जहां कलफदार वर्दी पहने सेवक चीज़ों को अदब से पेश करते हैं और अतिथिगण, बिना सेवकों की ओर देखे, बातों में मशगूल, चीज़ों को उदासीनता से मुंह में डाल लेते हैं। इन पार्टियों में वे मंत्री, विधायक और अधिकारी भी होते हैं जो इस गरीब देश के प्रतिनिधि और सेवक कहलाते हैं।

वर्जिश करके भी क्या कीजिएगा? अब बलिष्ठ शरीर का उतना महत्व नहीं रहा जितना पहले था। अब छुरे,चाकू,तमंचे का ज़माना है। तगड़े पहलवान साहब किसी सींकिये का चाकू खाकर अस्पताल का सेवन करते हैं और सींकिया अपनी हड्डियां फुलाये घूमता है। फिर यह परमाणु-युद्ध और स्टारवार्स का ज़माना है। कभी भी ज़िंदगी की रील कट सकती है। इसीलिए बादाम खाने और सेहत बनाने का कोई मतलब नहीं है। बीच में ही दुनिया ख़त्म हो गयी तो बादाम पर खर्च किये सारे पैसे बेकार हो जाएंगे।

लेकिन बादाम वर्जिश को छोड़ दें तो सर्दियों के दूसरे फायदे हैं। अगर आपके पास फटी कमीज़ है या कमीज़ों की कमी है तो सर्दी का मौसम आपके लिए बड़ा गरीबपरवर है। शर्त यह है कि आपके पास एक अदद कोट हो। मुझे ऐसे बहुत से सज्जन मिले जो फटी कमीज़ों का उपयोग जाड़े में कोट के नीचे कर लेते हैं। अगर आपका कोट खुले कॉलर वाला है तो कमीज़ का कॉलर साबित होना ज़रूरी है। अगर बंद गले का कोट है तो चिथड़ा हुई कमीज़ भी चलेगी।

मेरे एक मित्र सर्दियों में बिना बांह की कमीज़ पहनते थे। बांहें फट जाने पर वे उन्हें काट कर अलग कर देते थे और इन बंडी कमीज़ों को सर्दियों के लिए सुरक्षित रख लेते थे।

कुछ ऐसा ही कमाल वे मोज़ों में दिखाते थे। एक बार उन्होंने जूतों को अपने चरणों से अलग किया तो देखा मोज़ों का पंजों वाला हिस्सा ग़ायब है। हमारे ज्ञानवर्धन के लिए उन्होंने बताया कि मोज़े पंजों पर फट गये थे इसलिए उन्होंने पंजे वाला हिस्सा काट कर अलग कर दिया था। अब उनके मोज़ों की शक्ल उन 'एनक्लेट्स' जैसी हो गयी थी जिन्हें फुटबॉल के खिलाड़ी पहनते हैं। लेकिन जूते पहनने पर सब ठीक-ठाक दिखता था।

कुछ ऐसे महापुरुष भी मिले जो शेरवानी के नीचे सिर्फ बनियाइन पहनते थे। कमीज़ की खटखट ही नहीं। यह तो उनका बड़प्पन था जो बनियाइन पहन लेते थे। वह भी न पहनते तो उनका कोई क्या बिगाड़ लेता?

महिलाएं भी इस मौसम में फटे ब्लाउज़ को शॉल के नीचे चला लेती हैं। शॉल सबसे बढ़िया पैबंद का काम करता है। लेकिन शॉल केसाथ यह दिक्कत होती है कि उसे बराबर संभाले रखना ज़रूरी है। ज़रा सी असावधानी होने पर कलई खुल सकती है। कोट या शेरवानी के बटन बंद कर लेने पर निश्चिंत हुआ जा सकता है, लेकिन शॉल में यह सुविधा नहीं है।

जिन लोगों को सफाई से परहेज़ है, गंदे कपड़े पहनना सुहाता है, उनके लिए भी सर्दी का मौसम मददगार होता है। कोट के नीचे गंदे कपड़े भी उसी तरह चलते हैं जैसे फटे। लेकिन इसके लिए बंद कॉलर का कोट अनिवार्य है। कमीज़ से बदबू आने का ख़तरा हो तो कोट के ऊपर थोड़ा सेंट छिड़का जा सकता है। वैसे भी कई लोग नहाते कम और सेंट ज़्यादा छिड़कते हैं।

इस सब में अटपटा कुछ भी नहीं है क्योंकि आजकल ज़माना ऊपरी दिखावे का है। जितना दुनिया को दिखता है उतना ठीक रखो। मुलम्मा चमकदार होना चाहिए, भीतर सब चलता है। बहुत से कौवे सफेदी पोत कर हंस के रूप में पुज रहे हैं। इसीलिए बाहरी टीम-टाम ठीक रखो, भीतर कितना गंदा और जर्जर है इसकी चिंता छोड़ो।

लेकिन जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, सर्दियों का लाभ वे ही उठा सकते हैं जिनके पास एक अदद कोट या शेरवानी हो। जिनके पास सिर्फ फटी कमीज़ें हैं या जिन्हें सर्दियां नगर निगम के अलावों के बल पर काटनी हैं उनके लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं है। वहां समस्या क़मीज़ जुटाने की है, उसे छिपाने की नहीं।

पुण्यतिथि पर विशेष

सेवा, दृढ़ता व राष्ट्रीयता के प्रतीक थे डॉ. शंकर दयाल

सुरेश पचौरी

लेखक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री हैं।

अपने सुदीर्घ सार्वजनिक जीवन में मानवीय मूल्यों के जो मान और प्रतिमान डॉ. शर्मा ने प्रतिपादित किए, वे अनुकरणीय, प्रेरक और वंदनीय हैं। अपनी प्रतिभा, लगन, कर्मठता, निष्ठा और व्यक्तिगत जीवन में साफ-सुथरी छवि के साथ उन्होंने भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के शिक्षामंत्री, भोपाल के सांसद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, केन्द्रीय संचारमंत्री, आंध्रप्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल, भारत के उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति के सर्वोच्च पदों को सुशोभित किया। डॉ. शर्मा जिस पद पर भी रहे, उन्होंने अपनी कार्यकुशलता की अमिट छाप छोड़ी। डॉ. शर्मा अपने तपोनिष्ठ जीवन और निरभिमानी व्यक्तित्व के सदगुणों से जन-जन के चहेते बने। वे भारतीय संस्कृति पुरुष ही नहीं, बल्कि गंगा-जमुनी तहजीब के ऐसे प्रतिनिधि रहे हैं, जिनमें आरती और अजान के संयुक्त भाव विद्यमान थे। वे ज्ञानार्जन के लिए हर पल उत्सुक ज्ञानयोगी थे और राजयोगी भी थे। वे गुणी थे और गुणग्राहक भी थे। वे संविधान के अध्येता थे और उसके अनुरक्षक भी थे।

देश के 9वें राष्ट्रपति रहे डॉ. शंकर दयाल शर्मा की 26 दिसंबर को पुण्यतिथि है। जब हम उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हैं, तो हम एक ऐसे व्यक्तिव के योगदान को नमन करते हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सिद्धांतों, राष्ट्र-सेवा और संवैधानिक नैतिकता के उच्च मानकों को बनाए रखा। उनका जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल में हुआ व देहावसान 26 दिसंबर 1999 को दिल्ली में हुआ था।

अपने सुदीर्घ सार्वजनिक जीवन में मानवीय मूल्यों के जो मान और प्रतिमान डॉ. शर्मा ने प्रतिपादित किए, वे अनुकरणीय, प्रेरक और वंदनीय हैं। अपनी प्रतिभा, लगन, कर्मठता, निष्ठा और व्यक्तिगत जीवन में साफ-सुथरी छवि के साथ उन्होंने भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश के शिक्षामंत्री, भोपाल के सांसद, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, केन्द्रीय संचारमंत्री, आंध्रप्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल, भारत के उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति के सर्वोच्च पदों को सुशोभित किया। डॉ. शर्मा जिस पद पर भी रहे, उन्होंने अपनी कार्यकुशलता की अमिट छाप छोड़ी।

डॉ. शर्मा अपने तपोनिष्ठ जीवन और निरभिमानी व्यक्तित्व के सदगुणों से जन-जन के चहेते बने। वे भारतीय संस्कृति पुरुष ही नहीं, बल्कि गंगा-जमुनी तहजीब के ऐसे प्रतिनिधि रहे हैं, जिनमें आरती और अजान के संयुक्त भाव विद्यमान थे। वे ज्ञानार्जन के लिए हर पल उत्सुक ज्ञानयोगी थे और राजयोगी भी थे। वे गुणी थे और गुणग्राहक भी थे। वे संविधान के अध्येता थे और उसके अनुरक्षक भी थे।

डॉ. शंकर दयाल शर्मा कुशल शिक्षाशास्त्री थे। उन्होंने एम.ए. (हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी), उर्दू के आलिम फाजिल, एल.एल.एम., बार.एट.लॉ, डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (लंदन), एफआर.एस. (लंदन) एवं पी.एच.डी. (केम्ब्रिज) की शिक्षा अर्जित की। साथ ही उनके द्वारा बानडिन फेलोशिप ऑफ फारवर्ड स्कूल (अमेरिका) कानून में लिखी कई थीसिस आज भी मौलिक मानी जाती हैं। उन्होंने केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कानून भी पढ़ाया। वे लखनऊ विश्वविद्यालय में कानून के प्राध्यापक रहे हैं।

सन् 1949 में भोपाल रियासत के भारतीय संघ में विलीनीकरण आंदोलन की भागीदारी से लेकर 1992 में भारत के राष्टपति के सर्वोच्च पद पर पहुंचने तक की डॉ. शंकर दयाल शर्मा की यात्रा कथा पड़ाव-दर-पड़ाव, विविध अनुभवों से गुजरते चले जाने की एक ऐसी कहानी है जिसमें उनकी लगन, दृढ़ संकल्प, विद्वत्ता, संघर्षशीलता और कर्मठता का पग-पग पर परिचय मिलता है।

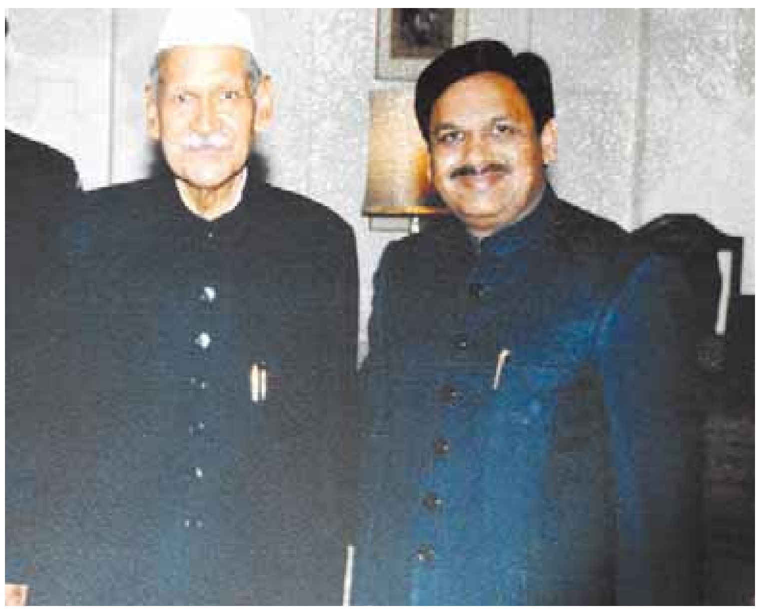

डॉ. शंकर दयाल शर्मा सन् 1952 से 1956 तक भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें आधुनिक भोपाल के निर्माता के रूप में सदा याद किया जाएगा। भोपाल के सर्वांगीण विकास में डॉ. शर्मा का अविस्मरणीय योगदान रहा है। डॉ. शर्मा की सूझबूझ भरी कोशिशों से भोपाल, मध्यप्रदेश की राजधानी बना। भोपाल में बीएचईएल का कारखाना लाने का श्रेय भी डॉ. शंकर दयाल शर्मा को है। इनके अलावा डॉ. शर्मा के अनवरत प्रयासों से भोपाल में गांधी मेडिकल कालेज, हमीदिया कालेज, रीजनल कालेज, मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कालेज जो अब मेनिट कहलाता है, जैसे बड़े शिक्षण संस्थान स्थापित हुए। डॉ. शंकर दयाल शर्मा के विशेष प्रयासों से भोपाल में 'ज्यूडिशल एकेडमी' बनी, जो पूरे देश में ज्यूडीशियरी के प्रशिक्षण को अनूठा संस्थान है।

डॉ. शर्मा का पूरा जीवन, राष्ट्र और राष्ट्रीयता एवं उनमें समाहित मूल्यों से ओतप्रोत रहा है। वे भारतीय संस्कृति की प्रतिमूर्ति रहे हैं। उनके जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव आये, पर उन्होंने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा। डॉ. शर्मा स्तरहीन, व्यक्तिगत राग-द्वेष की राजनीति एवं आलोचना-प्रत्यालोचना के प्रपंच से परे रहे। उनमें समय को पहचानने और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता थी। अपनों से अपनो के लिए लाभ नहीं लेना और विरोधियों को भी अपमानित नहीं करना, उनकी कार्यशैली रही है। डॉ. शंकर दयाल शर्मा सन् 1987 में सर्वसम्मति से भारत के उपराष्ट्रपति बने।

जुलाई 1992 में डॉ. शर्मा भारत के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के रूप में वे कई प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के साक्षी बने। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रथम बार जब वे भोपाल पहुँचे तो उन्होंने अपने सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह में बहुत ही भावुकता से मंतव्य प्रकट किया कि महान राष्ट्रपति कहलाने की मेरी चाह नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि चदरिया जस की तस रख सकूँ। डॉ. शर्मा का सार्वजनिक जीवन निष्कलंक रहा है। भोपाल की माटी के इस महान सपूत ने अपनी प्रखर बौद्धिक प्रतिभा और अध्यवसाय के सहारे अपने जीवन में जो कीर्ति कलश स्थापित किए, उन पर देश को गर्व है।

उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र नमन।

सम्यक सांस्कृतिक सोच के प्रतीक पंडित सीताराम त्रिपाठी

स्मृति लेख

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक भारत के राष्ट्रपति के ओएसडी रह चुके हैं एवं पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में चेयर प्रोफ़ेसर हैं।

आज जीवन स्तर को भले भ्रम में बहुत लोग अच्छा समझ रहे हों, लेकिन सामाजिक गिरावट बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। इससे भारत का बहुत नुकसान आने वाले समय में होगा। इस विकृत सोच पर वे काफी चिंतित रहते थे और कदाचित किसी बातचीत में अपनी बात बेझिझक कहते थे कि आने वाला समय बहुत ही दुरुहाताओं के साथ हमारे सामने दस्तक दे रहा है। अभी तक भारत को जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने सहेजा है, उसे सहेजने के लिए नई पीढ़ी में काफी जागरूकता की ज़रूरत होगी।

आज पंडित सीताराम त्रिपाठी जी की चौथी पुण्यतिथि है। जी मेरे पूज्य पिताश्री की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम उनके उन मूल्यों को स्मरण कर रहे हैं जो वे भारतीय सभ्यता व संस्कृति में स्थापित करना चाहते थे। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। लेकिन अब हमारे देश में भारतीय चित को लोग आर्टिफिसियल तरीके से गढ़ने लगे हैं। इससे हमारे देश में सांस्कृतिक क्षरण हो होगा। आज जीवन स्तर को भले भ्रम में बहुत लोग अच्छा समझ रहे हों, लेकिन सामाजिक गिरावट बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। इससे भारत का बहुत नुकसान आने वाले समय में होगा। इस विकृत सोच पर वे काफी चिंतित रहते थे और कदाचित किसी बातचीत में अपनी बात बेझिझक कहते थे कि आने वाला समय बहुत ही दुरुहाताओं के साथ हमारे सामने दस्तक दे रहा है। अभी तक भारत को जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने सहेजा है, उसे सहेजने के लिए नई पीढ़ी में काफी जागरूकता की ज़रूरत होगी।

ग्रामीण जीवन शैली में रचे-बसे पिताश्री ने समाज को सर्वदा महत्व दिया। वह भारतीय जीवन शैली की असली तस्वीर गाँव के छोटे-बड़े सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर में देखा करते थे।

अपने अतीत से कटते समाज में समय रहते समय का बोध कराना आवश्यक होता है। अपनी जड़ों से परिचय कराना आवश्यक होता है। अपने गाँव के वर्तमान को समझना भी आवश्यक होता है। अपने सीमित संसाधनों में जीवन जी लेने की भी आदतें यदि गाँव न रहें तो आज की पीढ़ी को समझ न आएगा। आज भी गाँव यह सीख देने में सक्षम हैं कि सीमित संसाधनों में कैसे जीवन को आनंद का विषय बनाया जा सकता है। भौतिकवादी युग में शहर तो भोगवादी संस्कृति की ओर ले जा रहे हैं। गांवों को भी अपने चपेट में ले रही उपभोगवादी संस्कृति अब अपने प्रभाव में लेने लगी है। गाँव में धोती व कुर्ता पहनना अब पिछड़ेपन की निशानी समझी जा रही है। विरले ही हैं जो धोती कुर्ता पहनते हैं। पिताश्री को धोती कुर्ता पसंद था। उनकी धोती की तहें जब एक के ऊपर एक बैठ जाती थीं और अपना शेप पाती थीं तो बहुत अच्छी लगती थीं। जब वह राष्ट्रपति भवन में रहे तब भी गाँव के लिवास को बहुत गर्व के साथ धारण करते थे। राष्टपति जी के साथ उनकी जो छवियाँ हमारे पास सुरक्षित हैं, उसमें वह भारतीय परिधान में सपरिवार कितने अच्छे दीखते हैं। उन्होंने धोती-कुर्ता को बहुत ही शान से धारण किया और वह उन परिधानों में बहुत खिलते थे। धोती-कुर्ता के ऊपर उनकी अच्छी सी नेहरू जैकेट उन पर बहुत ही फबती थी।

अपनी संस्कृति व सभ्यता में अपनी अस्मिता को बनाए रखने से परहेज करती पीढ़ी को काफी कुछ

सीखने के लिए संदेश ऐसे महामना हमें प्रदान करते हैं। उनकी चिंता थी कि जिस प्रकार आज सोशलाइजेशन हो रहा है और हम पश्चिम की ओर भाग रहे हैं, ये परिवर्तन हमारी भारतीय संस्कृति को ख़त्म कर देंगे। वे पश्चिम की चमक-धमक और उसके प्रभाव को समझते थे। वह यह चाहते थे कि लोग अपनी विरासत से जुड़कर रहें। उन्होंने अपने जीवन में विचारों से श्रेष्ठ होने का संदेश दिया। उन्होंने जीवन के कठिन दौर में भी वैचारिक शुचिता से समझौता कभी नहीं किया। सत्य ही उनके जीवन का सौन्दर्य था। अपने सार्वजानिक जीवन में या भारत सरकार के डाक विभाग में सेवारत रहते हुए पंडित सीताराम त्रिपाठी का जीवन अब भी सबकी स्मृतियों में इसलिए चिर-स्थायी बना हुआ है क्योंकि उन्होंने सदा भलाई की और सत्य के साथ मर्यादित जीवन जिया।

मुक्तिबोध का एक कथन स्मरण आता है कि आत्म-साक्षात्कार बहुत आसान है। यह साक्षात्कार वे ही कर पाते हैं जो जीवन में अनुशासन व सत्य के साथ जीते हैं। पिताश्री के श्रेष्ठ जीवन का जब अवलोकन हम आज करते हैं तो यही लगता है कि यदि उनके जीवन को कोई देखे तो यही कहेगा कि सच में आत्म-साक्षात्कार बहुत आसान है। और यह तभी होता है जब व्यक्ति का अंतस व वाह्य-जगत निर्विकार होता है। ऐसे महामना की पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन। वह हमें बताते हैं कि सहज जीवन में कोटिशः सम्यक दृष्टि व सम्यक सोच विद्यमान होती हैं।

वीर बाल दिवस पर विशेष

मिट गए पर झुके नहीं अमर बलिदानी साहिबजादे

योगेश कुमार गोयल

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

9 जनवरी 2022 को गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चारों साहिबजादों के साहस और देशभक्ति के साहसिक कार्यों से जन-जन को परिचित कराने तथा प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 26 दिसम्बर को यह दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि माता गुजरी, गुरु गोबिंद सिंह और उनके चारों साहिबजादों की बहादुरी और आदर्शों ने लाखों लोगों को ताकत दी, जिन्होंने कभी भी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया, समावेशी और सौहार्द्रपूर्ण विश्व की कल्पना की। गुरु गोबिंद सिंह के चारों साहिबजादों ने अन्याय के आगे सिर झुकाने के बजाय अपने देश, अपने धर्म की रक्षा के लिए हंसते-हंसते अपना बलिदान कर अपनी वीरता और अपने आदर्शों से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए, जो आज भी हर किसी के लिए अनुकरणीय हैं। ऐसे में उनकी शहादत को जितना भी नमन किया जाए, कम होगा।

गुरु गोबिंद सिंह जी के चार छोटे साहिबजादों के बलिदान की याद में 'वीर बाल दिवस' 26 दिसम्बर को मनाया जाता है, जो सही मायनों में इन वीर बालकों की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि है। दरअसल इन चारों वीर बालकों ने छोटी उम्र में ही न केवल गजब की वीरता दिखाई बल्कि अपने धर्म के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी थी। वीर बाल दिवस वही दिन है, जब साहिबजादों 9 वर्षीय जोरावर सिंह और 6 वर्षीय फतेह सिंह को मुगलों द्वारा दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था और अपनी जान देकर भी उन्होंने अपने धर्म को सुरक्षित रखा। 9 जनवरी 2022 को गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चारों साहिबजादों के साहस और देशभक्ति के साहसिक कार्यों से जन-जन को परिचित कराने तथा प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 26 दिसम्बर को यह दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि माता गुजरी, गुरु गोबिंद सिंह और उनके चारों साहिबजादों की बहादुरी और आदर्शों ने लाखों लोगों को ताकत दी, जिन्होंने कभी भी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया, समावेशी और सौहार्दपूर्ण विश्व की कल्पना की। गुरु गोबिंद सिंह के चारों साहिबजादों ने अन्याय के आगे सिर झुकाने के बजाय अपने देश, अपने धर्म की रक्षा के लिए हंसते-हंसते अपना बलिदान कर अपनी वीरता और अपने आदर्शों से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए, जो आज भी हर किसी के लिए अनुकरणीय हैं। ऐसे में उनकी शहादत को जितना भी नमन किया जाए, कम होगा।

गुरु गोबिंद सिंह ने देशवासियों को अपने धर्म के प्रति जागरूक होने तथा धर्म परिवर्तन नहीं करने के लिए काफी प्रेरित किया और मुगलों के खिलाफ लड़ाई में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। गुरु गोबिंद सिंह और उनका पूरा परिवार सिख धर्म का प्रतीक था, जिन्होंने सिख धर्म को आगे बढ़ाने का कर्त्तव्य अपने हाथों में लिया था। उनका एक ही प्रण था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे लोगों को धर्म परिवर्तन नहीं करने देंगे और मुगलों के खिलाफ एकता से लड़ेंगे। यही कारण था कि मुगलों द्वारा गुरु गोबिंद सिंह और उनके परिवार को धर्म परिवर्तन करने के लिए अनेक कष्ट दिए गए। उनके दो बड़े बेटों अजीत सिंह और जुझार सिंह को उनके सामने ही मार डाला गया और दो छोटे बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार

में चुनवा दिया गया लेकिन गुरु गोबिंद सिंह ने सिख धर्म छोड़कर मुगल बनना कभी स्वीकार नहीं किया। सिखों के 10वें गुरु और उनके चारों साहिबजादों की महानता इसी से स्पष्ट परिलक्षित होती रही है कि इन महान हस्तियों ने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय बेहद कष्टदायक मौत को चुना।

मुगल सेना द्वारा अचानक आक्रमण किए जाने पर गुरु गोबिंद सिंह को पूरे परिवार के साथ 20 दिसम्बर 1704 को कड़कड़ाती ठंड में आनंदपुर साहिब किला छोड़ना पड़ा था। किले को छोड़कर जब वे सरसा नदी को पार कर रहे थे तो नदी में पानी के तेज बहाव के कारण उनके परिवार के सदस्य एक-दूसरे से बिछुड़ गए। उनके दोनों बड़े बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह उनके साथ रह गए और चमकौर पहुंच गए जबकि उनकी माता गुजरी तथा दोनों छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह अलग हो गए, जिनके साथ गुरु गोबिंद सिंह का निजी सेवक गंगू था। गंगू माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को उनके परिवार से मिलाने का भरोसा देकर अपने गांव सहेड़ी ले गया और चंद सोने की मोहरों के लालच में इसकी खबर सरहिंद के नवाब वजीर खान को कर दी, जिसके बाद माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को मुगलों द्वारा गिरफ्तार कर लिया। साहिबजादों को जब वजीर खान के समक्ष पेश किया गया तो उसने उन्हें सिर झुकाकर खड़ा होने और इस्लाम धर्म अपनाने को कहा लेकिन इतने छोटे होकर भी दोनों ने सिर झुकाने और इस्लाम धर्म को अपनाने से इन्कार करते हुए कहा कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी और के समक्ष सिर नहीं झुकाते। उसके बाद वजीर खां ने दोनों बच्चों को काफी ललचाया, डराया, धमकाया लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। आखिरकार क्रूर वजीर खान ने दोनों को दीवार में जिंदा चुनवाने का आदेश दे डाला। जब उन्हें दीवार में चुना जाने लगा तो दोनों साहिबजादे जपुजी साहिब का पाठ करने लगे।

आखिरकार 26 दिसम्बर 1705 को 6 साल के फतेह सिंह और 9 साल के जोरावर सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया और इस प्रकार दोनों साहिबजादों ने अपने धर्म की खातिर हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। दोनों इतने वीर बालक थे कि दीवार पूरी बन जाने के बाद भी अंदर से इनके जयकारा लगाने की आवाजें आती रही। कहा जाता है कि माता गुजरी को भी सरहिंद के किले से धक्का देकर मार डाला गया था। गुरु गोबिंद सिंह को जब इस घटनाक्रम के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी माता और छोटे साहिबजादों की शहादत से दुखी होने और मुगलों के अत्याचारों के समक्ष घुटने टेकने के बजाय औरंगजेब को एक जफरनामा (विजय पत्र) लिखा, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को स्पष्ट चेतावनी दे डाली तुम्हारे साम्राज्य को समाप्त करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो चुका है। गुरु गोबिंद सिंह के सबसे बड़े बेटे थे अजीत सिंह, जिन्होंने चमकौर के युद्ध में केवल 17 साल की आयु में ही मुगल फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। तीर खत्म होने पर उन्होंने तलवार निकालकर दुश्मनों से युद्ध किया लेकिन युद्ध के दौरान तलवार टूट जाने पर वे वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत के बाद गुरु जी के दूसरे बेटे जुझार सिंह ने रणभूमि में मोर्चा संभाला और अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए वे भी वीरगति को प्राप्त हुए। गुरु गोबिंद सिंह की वीरता और धर्म की रक्षा के लिए उनके बलिदान को तो पूरी दुनिया जानती है लेकिन उनके साहिबजादों की वीरता और बलिदान को आज की पीढ़ी कम ही जानती है, इसलिए उनकी वीरता और बलिदान को सम्मान देना अत्यंत जरूरी है। खेलने-कूदने की छोटी सी उम्र में उनका यह बलिदान आज की युवा पीढ़ी को अपने देश और धर्म से प्रेम करने और इनकी रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तत्पर रहने का संदेश देता है। यह समय की मांग भी है कि ऐसे महान वीर बालकों का बलिदान व्यर्थ न जाए और लोगों को उनके साहस, न्याय स्थापना की उनकी कोशिश तथा बलिदान के बारे में पता चले और उनके बलिदान से लोग प्रेरित हों।

विभिन्न खेलों के विजेता खिलाड़ियों को सांसद खेल महोत्सव के पुरस्कार किए वितरित

अटलजी की जयंती सुशासन दिवस पर सांसद खेल महोत्सव का हुआ समापन

बैतूल। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटलबिहारी वाजपेई की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाते सांसद खेल महोत्सव 2025 का समापन समारोह 25 दिसंबर को शहर के छत्रपति शिवाजी ओपन ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। समापन कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके, आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे, घोड़ाडोंगरी विधायक गंगाबाई उईके, मप्र जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष मोहन नागर, नपाध्यक्ष बैतूल पार्वतीबाई बारस्कर, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य सुधाकर पवार, बैतूल सुधार न्यास के पूर्व अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ स्व. अटल जी एवं भगवान बिरसा मुंडा के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर शासकीय कन्या शाला की छात्राओं द्वारा जनजातीय नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी गई। साथ ही मल्लखंब अभ्यास एवं प्रदर्शन ने दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित किया। कार्यक्रम के दौरान कुल 17 खेलों, जिनमें बास्केटबॉल, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, रस्साकसी, पिट्ठू, फुटबॉल, तैराकी, योगासन, स्केटिंग सहित अन्य खेल शामिल है, के फाइनल मुकाबलों के विजेताओं और उपविजेताओं तथा व्यक्तिगत खेलों के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को सांसद खेल महोत्सव के पुरस्कार भी वितरित किए गए।

केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके ने इस अवसर पर कहा कि भारत खेल, उद्यमिता, उद्योग, तकनीक, अंतरिक्ष और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा विश्व के सामने मनवाएगा। उन्होंने सांसद खेल महोत्सव की जानकारी देते बताया कि यह आयोजन 21 सितंबर से प्रारंभ होकर 25 दिसंबर तक ग्राम स्तर से लेकर संसदीय लोकसभा स्तर तक आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है, जो युवाओं को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाती है। इस अवसर पर उन्होंने सभी खिलाड़ियों, खेल अधिकारियों, प्रशिक्षकों तथा आयोजन में विशेष योगदान देने वाले सांसद खेल महोत्सव के नोडल खेल अधिकारी सुबोध शर्मा एवं शिक्षा विभाग के जिला खेल अधिकारी धर्मेंद्र पवार सहित सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।

पूरे देश के लिए प्रेरणा का केंद्र बना सांसद खेल महोत्सव- जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष मोहन नागर ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव आज पूरे देश के लिए प्रेरणा का केंद्र बन चुका है। प्रधानमंत्री का संदेश है कि खेल हमें जीत के साथ-साथ हार से सीख लेना भी सिखाते हैं। 2030 में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेलों को ध्यान में रखते हुए यदि खिलाड़ी निरंतर अभ्यास, अनुशासन और समर्पण से प्रशिक्षण लें, तो वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उन्होंने मेजर ध्यानचंद का उदाहरण देकर निरंतर मेहनत और जुनून के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

सांसद खेल महोत्सव के तहत 1 लाख 9 हजार 913 खिलाड़ियों ने किए पंजीयन- जिला सलाहकार समिति सदस्य सुधाकर पवार ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत हमारे क्षेत्र से कुल 1 लाख 9 हजार 913 पंजीयन हुए हैं, जो कि पूरे देश में चौथे स्थान पर रहा। यह हमारे पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद श्री उइके का आभार व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को किया संबोधित

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेरिस से वर्चुअल माध्यम द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया। जिसका लाइव प्रसारण कार्यक्रम स्थल पर देखा गया । प्रधानमंत्री ने सांसद खेल महोत्सव में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से संवाद कर उनके खेल अनुभवों की जानकारी ली तथा उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित कर उनकी प्रतिभा को निखारने का सशक्त माध्यम हैं।

बैतूल टीम को मिला प्रथम पुरस्कार

बैतूल गर्ल्स व बैतूल बॉयज की टीम बास्केटबॉल में बनी विजेता

गौरतलब है कि सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत गत रविवार 21 दिसंबर को पूरे जिले के सभी विकासखंडों की टीमों के बीच फाइनल मुकाबलों का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता बनी टीमों को मुख्य अतिथि द्वारा आज पुरस्कार राशि के साथ ट्रॉफी, मेडल एवं सर्टिफिकेट देकर मंच पर सम्मानित किया। समापन समारोह के दौरान बैतूल बास्केटबॉल टीम के कोच दीपक पवार ने बताया कि बास्केटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में बैतूल गर्ल्स एवं बैतूल

बॉयज की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुलताई की टीम को हराकर विजेता का खिताब हासिल किया। बैतूल गर्ल्स टीम की नंदिनी, इशिता द्विवेदी, पिंकी साकरे, लोकमती, अंजली, योगिता, आर्या, आराध्या, साक्षी एवं रेवा को मंच पर मुख्य अतिथि द्वारा मेडल पहनाकर, ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। वहीं बैतूल बॉयज बास्केटबॉल टीम के नीतेश, राघवेंद्र, वंश, शौर्य, सारांश, अमन, दिव्यांश, कृष्णा, तेजस एवं कृश को मेडल पहनाकर, ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र तथा नगद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांसद खेल महोत्सव के नोडल खेल अधिकारी सुबोध शर्मा एवं शिक्षा विभाग के जिला खेल अधिकारी धर्मेन्द्र पवार ने बैतूल बॉयज एवं बैतूल गर्ल्स टीम के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी तथा बैतूल बास्केटबॉल टीम के कोच दीपक पवार के प्रशिक्षण की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी और आभार व्यक्त किया।

सप्रे संग्रहालय में अलंकरण समारोह

पत्रकार की पैनी दृष्टि ही जमीनी हकीकत से करा सकती है परिचित

भोपाल। एक पत्रकार ही ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी पैनी नजर से समाज में खुद भी कुछ बन सकता है और दूसरे को भी कुछ बना सकता है। इसकी वजह जमीनी वास्तविकता तक पहुंचने की उसकी क्षमता होती है। समय और समाज की नब्ज पर पत्रकारों की ही पकड़ होती है। समाज के दीगर क्षेत्रों के लोग जो समझ नहीं पाते उसे पत्रकार सहज ही समझ लेता है।

यह कहना है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत का। वे गुरुवार को माधवराव सप्रे संग्रहालय में आयोजित 'संवाद एवं अलंकरण समारोह' में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर ने की। समारोह में तीन वरिष्ठ पत्रकारों को 'हुक्मचंद नारद' सम्मान से सम्मानित किया गया। इस दौरान सम्मानित पत्रकारों ने अपने पत्रकार जीवन के अनुभवों को भी साझा किया।

अपने उद्बोधन में रावत ने कहा कि अपने सेवाकाल में कलेक्टर, संचालक जनसंपर्क या मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे पद संभालने के दौरान पत्रकारिता जगत के लोगों का साथ रहा। इस दौरान बहुत कुछ सीखा-समझा। उन्होंने जबलपुर नगर निगम चुनाव के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में प्राप्त अनुभव को साझा करते हुए बताया कि उस चुनाव में महापौर पद पर जिस दल के प्रत्याशी को जीत मिली उस दल की परिषद गठित नहीं हो पाई। वहीं, थर्ड जेंडर के कुछ प्रत्याशियों को भी जीत मिली। इस स्थिति पर वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह ने जो विश्लेषण दिया उसमें बताया कि 'जनता मन बना चुकी थी कि स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों को ही मत देंगे। इसी का परिणाम यह निकला कि कुछ क्षेत्रों में राजनेताओं से ऊबकर ही किन्नरों को भी प्रतिनिधि चुना'। यह एक पत्रकार की दृष्टि है।

अध्यक्षीय उद्बोधन में अभिलाष खांडेकर ने कहा कि यह दौर तकनीक का दौर है, ऐसे समय में पत्रकारिता के सामने चुनौतियां भी बदलीं हैं। जमीनी सच्चाई को समझने वाला पत्रकार ही सफल पत्रकार हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सम्मान समारोह जहां सम्मानित पत्रकारों में दायित्वबोध जगाते हैं तथा नए पत्रकारों को प्रेरणा भी देते हैं।

इसके पूर्व संग्रहालय के संस्थापक निदेशक विजयदत्त श्रीधर ने स्वागत वक्तव्य तथा आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पत्रकारों के सम्मान के बहाने हम उनके अनुभवों को जानें-समझें। उनकी इस यात्रा से परिचित हो सकें। जिनके नाम से सम्मान स्थापित है, उन विभूति 'हुक्मचंद नारद' का परिचय देते हुए बताया कि वे मप्र के पहले वेतनभोगी पत्रकार थे। वे अपने कार्यों के बल पर संस्कारधानी जबलपुर की पहचान बने थे। इसके साथ ही उन्होंने सम्मानित तीनों पत्रकारों का परिचय देते हुए कहा कि ऐसी विभूतियों को सम्मानित कर समाज भी गौरव का अनुभव करता है। आरंभ में संग्रहालय के अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार अवस्थी ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन और आभार प्रदर्शन पत्रकार अजय बोकिल ने किया।

'यूके' में भी ऐसा संस्थान नहीं- मुख्य अतिथि ओपी रावत ने कहा कि सप्रे संग्रहालय की खुश्बू देश के बाहर भी है। यहां जिस तरह से सामग्री का 'डिजिटाइजेशन' हुआ उसकी गूंज यूके तक में सुनाई दी है। उन्होंने बताया कि वहां के एक मित्र ने इस संग्रहालय के बारे में जानकारी मांगी और कहा कि ऐसा कार्य हमारे यहां भी नहीं हुआ।

इनका हुआ सम्मान- कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार एन. के. सिंह, चंद्रकांत नायडू तथा राजेन्द्र हरदेनिया को 'हुक्मचंद नारद सम्मान' से सम्मानित किया गया। सम्मान के तहत शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

सम्मान के बाद अपने अनुभव साझा करते हुए वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह ने सक्रिय पत्रकारिता के दौरान की गई रिपोर्टिंग के संस्मरण सुनाये। उन्होंने बताया कि जब वर्ष 1984 में भोपाल में गैस हादसा हुआ था, उसके दूसरे दिन पूरे शहर में घूम-घूम कर रिपोर्टिंग की। तब वहां का दृश्य इतना हृदय विदारक था कि शाम को जब खबर लिख रहा था तो हर शब्द पर मेरे आंसू टपक रहे थे।

शासकीय संगीत महाविद्यालय धार में चार दिवसीय तबला कार्यशाला का आयोजन किया गया

धार। तबला दिवस के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा तबला कार्यशाला पर केन्द्रित सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुखता से आयोजन किया गया। शासकीय संगीत महाविद्यालय धार में 22 दिसम्बर से 25 दिसम्बर तक चार दिवसीय तबला कार्यशाला का आयोजन किया गया।

महाविद्यालय प्राचार्या श्रीमती कांति तिर्की ने बताया कि इस तबला कार्यशाला में 60 प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की। इस कार्यशाला का मुख्य विषय भारतीय संगीत की तबला वादन की प्रारम्भिक विधि और कार्यशाला में तबला वादन के विविध तरीके शामिल थीं। कार्यशाला में भोपाल के प्रसिद्ध तबला वादक मनोज पाटीदार प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यशाला में प्रतिभागियों को प्रारंभिक तालाभ्यास, कायदे , रेला एवं फ्रेज इत्यादि का अभ्यास कराते हुए प्रशिक्षण दिया। तबला दिवस के अवसर पर उभरते कलाकार मनोज पाटीदार ने मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति दी, जिसमें तालों के राजा तीनताल की एकल वादन में उठान, पेशकार, विभिन्न घरानों के कायदे, रेले, रौ, टुकड़े, चक्करदार इत्यादि का अद्भुत प्रर्दशन किया। तबला दिवस पर कार्यशाला में प्रतिभागी छात्रों द्वारा भी समूह और एकल वादन की प्रस्तुति दी गई और तबला दिवस की कार्यशाला संपन्न की । इस कार्यशाला में विद्यार्थी एवं श्रोता गण लाभान्वित हुए । साथ ही उन्होंने बताया कि तबला वादन की शिक्षा हेतु वादन के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान अर्जन, मेहनत और लगन अत्यन्त आवश्यक है। संगीत के आयामों को युवा पीढ़ी के लिए ज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है ,जिससे हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखा जा सके, संगीत की समृद्ध परंपरा को समृद्ध किया जा सके।

इस अवसर पर महाविद्यालय के जनभागीदारी अध्यक्ष दीपक ख़लतकर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने संगीत का एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु कार्यशाला की महत्ता पर प्रकाश डाला । इस कार्यशाला में महाविद्यालय स्टाफ भी उपस्थित रहा। सोमत सिंह चिडार, शशि चौधरी, रविन्द्र डोडवे, डॉ देशराज वशिष्ठ, प्रिया शर्मा, पंकज राठौर, मनीष खसरावल, श्रोतागण उपस्थित रहे।

उज्जैन में हुए परिचय सम्मेलन में धार की टीम हुई शामिल

10 व 11 जनवरी को होने वाले परिचय सम्मेलन का हो रहा व्यापक प्रचार

धार। उज्जैन में अग्रवाल जेजीस द्वारा आयोजित दो दिवसीय अग्रवाल युवक-युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें धार में 10 व 11 जनवरी को आयोजित होने वाले परिचय सम्मेलन की टीम के आशीष गोयल,अनूप अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, पायल आशीष गोयल, चंदा शैलेंद्र अग्रवाल, अर्चना सुनील अग्रवाल,ओम प्रकाश अग्रवाल,गोपीकिशन अग्रवाल, मनीष अग्रवाल,दीपक अग्रवाल दीपश्री राजेश मित्तल,राजेंद्र अग्रवाल दीपक अग्रवाल अंबिका सेल्स, अवंती ओम प्रकाश अग्रवाल, कविता गोपी किशन अग्रवाल, वर्षा राजेंद्र अग्रवाल शामिल हुए ।

मध्यप्रदेश अग्रवाल महासभा धार द्वारा अग्रवाल समाज धार के सानिध्य में दो दिवसीय आयोजित अखिल भारतीय विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन धार स्थित श्रद्धा शगुन गार्डन में 10 एव 11 जनवरी को होगा जिसको लेकर अग्रबन्धुओ में भारी उत्साह देखा जा रहा है वही युवक एवं युवतियों की परिचय पुस्तिका में एंट्री का अंतिम दौर चल रहा है अभी तक 700 इंट्री प्राप्त हो चुकी है। जानकारी मीडिया प्रभारी अशोक मित्तल एव श्याम मंगल लेबड़ ने दी।

एसआईआर के बाद 62737 मतदाताओं के नाम हटाये

जिले में अब रह गये 11 लाख 95 हजार 558 मतदाता, सबसे ज्यादा आमला विस से हटे नाम

बैतूल। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) में डोर-टू-डोर सर्वे के बाद जिले के 62,737 मतदाताओं के नाम हटे है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन मतदाताओं में से कई की मृत्यु हो चुकी है और अनुपस्थित पाए गए है। इसके अलावा स्थानांतरित हो गये या रिपीट नाम है। 6995 मतदाताओं की मौपिंग नहीं हो पाई है। अब नो मैपिंग वाले मतदाताओं को सूचना पत्र जारी किए जा रहे है। प्रशासन ने प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन भी कर दिया है। इसका अवलोकन 22 जनवरी 2026 तक किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक सुधारों के लिए आवेदन भी दिए जा सकते हैं। बता दे कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और कटवाने की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। ऐसे मतदाता जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की हो गई है या हो रही है, वे प्रारूप 6 में घोषणा पत्र के साथ आवेदन कर सकते है। यदि पूर्व में अन्य विधानसभा क्षेत्र या मतदान केन्द्र में नाम दर्ज है और उसे अन्य मतदान केन्द्र में नाम जुड़वाना है तो प्रारूप 8 में आवेदन करना होगा। मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि में सुधार करना है तो प्रारूप 8 में आवेदन करना होगा। इसके अलावा विलोपन के लिए प्रारूप 7 में आपत्ति पेश की जा सकती है।

एसआईआर के बाद बचे 11 लाख 95 हजार मतदाता- एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले जिले में 12 लाख 58 हजार, 295 मतदाता थे। इनमें मुलताई में 2 लाख 35 हजार 605, आमला में 2 लाख 19 हजार 778, बैतूल में 2 लाख 62 हजार 061, घोड़ाडोंगरी में 2 लाख 69 हजार 767 और भैंसदेही में 2 लाख 71 हजार 084 मतदाता शामिल थे। एसआईआर की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है और प्रशासन द्वारा मतदाता सूची का प्रकाशन भी कर दिया गया है। अब जिले की मतदाता सूची में 11 लाख 95 हजार 558 मतदाता रह गये है। इनमें मुलताई में 2 लाख 24 हजार 440, आमला में 2 लाख 01 हजार 297, बैतूल में 2 लाख 48 हजार 387, घोड़ाडोंगरी में 2 लाख 59 हजार 467 और भैंसदेही में 2 लाख 61 हजार 967 मतदाता शामिल हैं। जिले में कुल मतदाताओं में 6 लाख 9 हजार 515 पुरूष और 5 लाख 86 हजार 027 महिलाएं एवं 16 अन्य मतदाता शामिल है।

जिले में 62737 मतदाता कम हुए है। इनमें सबसे ज्यादा 18481 मतदाता आमला में कम हुए है। वहीं सबसे कम 9117 मतदाता भैंसदेही विधानसभा में कम हुए है। मुलताई में 11165, बैतूल में 13674 और घोड़ाडोंगरी में 10300 मतदाता कम हुए है। जिले में मतदाता सूची में जो 62,373 मतदाता कम हुए है, उनमें 15800 मतदाताओं की मृत्यु होने से, 4403 मतदाता मिले नहीं या अनपुस्थित पाए गये है।

अटलजी की 101वीं जयंती स्मृति पर्व पर भाजपा ने 18 मंडलों के सभी बूथ केंद्र पर स्वच्छता अभियान एवं दीपोत्सव उत्सव कर 'सुशासन दिवस' मनाया

भाजपा कार्यकर्ताओं ने 'भारत रत्न' श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया

धार। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के निर्धारित कार्यक्रम अनुसार भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती के मार्गदर्शन में जननायक, भारतीय राजनीति के अजातशत्रु, ओजस्वी व प्रखर वक्ता, पूर्व प्रधानमंत्री, 'भारत रत्न' श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष अटल स्मृति पर्व के तहत जिले की तीन विधानसभा 18 मंडलों के सभी बूथ केंद्र पर पूर्व संध्या पर दीपोत्सव व 25 दिसंबर को भाजपा नगर मंडल कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित उन्हें कोटि-कोटि नमन एवं 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाया।

इस दौरान भाजपा नेता डॉ शरद विजयवर्गीय, जिला महामंत्री देवेंद्र सोनाने ,पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ममता जोशी ने अटल जी के चित्र पर मल्यार्पण कर उन्हें याद किया।

भाजपा नेता डॉ शरद विजयवर्गीय ने कहा कि अटल जी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलना है- सुशासन, लोकतंत्र की मजबूती,

राष्ट्रप्रथम की भावना एवं सदैव मुस्कुराते रहने का संदेश आज भी प्रासंगिक है। उनके आदर्शों पर चलकर हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करेंगे।

जिला महामंत्री देवेंद्र सोनोने ने कहा कि अटल जी ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व में उन्होंने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए उनके प्रयासों को सदैव स्मरण किया जाएगा।

श्रीमती ममता जोशी ने कहा कि श्रद्धेय अटलजी माँ भारती की आत्मा की सशक्त आवाज थे, उनके विचारों और कार्यों में राष्ट्रभक्ति एवं जनसेवा सदा के लिए जुड़ी थी। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ लोकतंत्र की सशक्ति, राजनीति में शुचिता और सुशासन के उनके स्वप्न मोदी सरकार में साकार हो रहे हैं।

इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष राखी राय, कार्यालय मंत्री मनीष प्रधान,जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा,मंडल अध्यक्ष जयराज देवड़ा,अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष पूनमचंद फकीरा, मंडल महामंत्री सीमा सोनी,राकी आहूजा,सुरेश प्रजापत, कैलाश पिपलोदिया, युवा मोर्चा जिला मंत्री जसप्रीत डंग ,राकेश दुर्गेश्वर अनिल गेहलोद, महेश बोडाने , बादल मालवीय, कल्पना जोशी ,सीमा पंडया अनुसुइया वैष्णव, डाली जाधव, नमन रावल, मीना दुबे,गौरव जाट, अंकित जैन अजय राठौर, रितेश अग्निहोत्री, नवीन भंवर, जय सूजान,जतिन मौर्य, पंकज जाधव ,भय्यु राम,हरीश आर्य, देवांग पवार, लखन शर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्मरण कर अटलजी को पुष्पांजलि अर्पित की।

राजनैतिक दलों की बैठक अनमैप मतदाताओं को 02 जनवरी 2026 से 09 फरवरी 2026 तक नोटिस

सीहोर (निप्र)। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वृंदावन सिंह की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। सीहोर जिले के प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चारों विधानसभाओं के ड्राफ्ट रोल की प्रतियां प्रदान की गई।

बैठक में उन्होंने जानकारी दी कि ड्रॉफ्ट रोल के अनुसार जिले की चारों विधानसभाओं में 983143 मतदाता है, जिसमें 510716 पुरुष मतदाता 472405 महिला मतदाता तथा 22 अन्य मतदाता शामिल हैं। बुधनी विधानसभा में कुल 269068 मतदाता है, जिसमें 140245 पुरुष तथा 128817 महिला एवं 06 अन्य मतदाता शामिल है। आष्टा विधानसभा में 144382 पुरुष मतदाता 133775 महिला मतदाता तथा 03 अन्य मतदाता, इस प्रकार कुल 278160 मतदाता हैं। इछावर विधानसभा में 224927 कुल मतदाता है, जिसमें 117574 पुरुष मतदाता तथा 107346 महिला मतदाता तथा 07 अन्य मतदाता शामिल हैं। सीहोर विधानसभा में कुल 210988 मतदाता हैं, जिसमें 108515 पुरुष मतदाता तथा 102467 महिला मतदाता एवं 06 अन्य मतदाता शामिल है।

भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के उपरांत मतदान केंद्रो की संख्या बढ़कर 1367 हो गई है। पहले 1257 थी इन बढ़े हुए मतदान केंद्रो से सभी मतदाता मैप हो गए हैं। चारों विधानसभाओं में 11335 मतदाता ऐसे हैं जो 2003 की मतदाता सूची से मैप नहीं हो पाए हैं। बैठक में एसडीएम श्री तन्मय वर्मा, भाजपा के श्री जलज छोकर, कांग्रेस के श्री केके रिछारिया बसपा के बसपा के श्री नरसिंह भारतीय उपस्थित थे।

ऑन मैप मतदाताओं से दावे आपत्ति और सुनवाई के लिये

अनमैप मतदाताओं को 02 जनवरी 2026 से 09 फरवरी 2026 तक नोटिस जारी किए जाएंगे। बुधनी विधानसभा क्षेत्र के अनमैप मतदाताओं की सुनवाई के लिए बुधनी, भेरूंदा तथा रेहटी एवं आष्टा विधानसभा के अनमैप मतदाताओं के लिए आष्टा एवं जावर तथा इछावर विधानसभा के अनमैप मतदाताओं के लिए इछावर और सीहोर विधानसभा के अनमैप मतदाताओं के लिए सीहोर एवं श्यामपुर में दावे आपत्ति लिए जाएंगे

अनमैप मतदाताओं की सुनवाई एवं दस्तावेज प्राप्त करना

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार 2003 की मतदाता सूची में मैपिंग की जानकारी देना-उस स्थिति में कोई दस्तावेज नहीं देना है। बीएलओ ने भी जो मैपिंग की है उन्हें भी कोई दस्तावेज नहीं देना है। यदि मतदाता उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह अपना जवाब एवं दस्तावेज बीएलओ को दे सकते हैं। जवाब एवं दस्तावेज प्रदान करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों को अधिकृत कर सकते हैं।

नवीन फॉर्म 6 , 7 एवं 8 प्रस्तुत करना

नवीन मतदाता फॉर्म 6 प्रस्तुत कर सकते हैं। दस्तावेज एवं घोषणा फार्म 08 भी प्रस्तुत कर सकते हैं। निरसन के लिए फॉर्म 7 प्रस्तुत किया जाना। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के बीएलए 10 फॉर्म बीएलओ को दे सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

जिन मतदाताओं का नाम 2003 की सूची से लिंक नहीं हो रहा है ऐसे मतदाता 01 जुलाई 1987 के पहले जन्म हुआ हो वह स्वयं का जन्म प्रमाण पत्र या जन्म से जुड़े दस्तावेज तथा 01 जुलाई 1987 और 2 दिसम्बर 2004 के मध्य जिनका जन्म हुआ है, वह स्वयं का जन्म प्रमाण पत्र, माता या पिता का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार 2 दिसम्बर 2004 के बाद जन्म हुआ है वह स्वयं का जन्म प्रमाण पत्र, पिता का जन्म प्रमाण पत्र, माता का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा

दस्तावेजों की सांकेतिक सूची

दस्तावेजों की सांकेतिक जानकारी किसी केंद्रीय /राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम या नियमित कर्मचारी /पेंशनर्स को जारी पहचान पत्र /पेंशन भुगतान आदेश/भारत में किसी सरकारी /स्थानीय निकाय /बैंक/ डाकघर /एलआईसी। सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 07 जुलाई 1987 से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जान प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, किसी मान्यता प्राप्त कोई बोर्ड। विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी एवं अन्य जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां पर उपलब्ध होए राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी/भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार के लिए आयोग के पत्र क्रमांक 23/2025 ईआरएस दिनांक 09.09.2025 द्वारा जारी निर्देशानुसार लागू होंगे।

किसान क्रेडिट कार्ड बनने से खुश हैं वनाधिकार पट्टाधारी जनजातीय किसान, अब कृषि कार्य हेतु ऊंची ब्याज दर पर नहीं लेना पड़ता ऋण

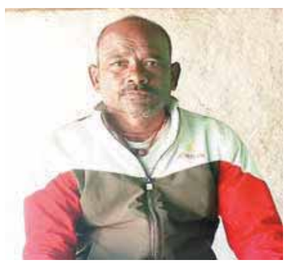

रायसेन (निप्र)। प्रदेश में वनाधिकार पट्टाधारी जनजातीय वर्ग के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सहित सरकार की कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। रायसेन जिले में 5316 वनाधिकार पट्टाधारी जनजातीय किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए हैं। रायसेन जिले के सांची जनपद के ग्राम रतनपुर निवासी वनाधिकार पट्टाधारी किसान श्री रूपबसंत आदिवासी भी किसान क्रेडिट कार्ड मिलने से बेहद खुश हैं। हितग्राही रूपबसंत ने बताया कि वर्षो से काबिज भूमि का अधिकृत स्वामित्व पट्टा नहीं होने से किसानों को मिलने वाली सरकार की योजनाओं सस्ता और आसान कर्ज, बीज, खाद, फसल बीमा सहित अन्य सुविधाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा था। खेती के लिए साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता था। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित एमपी वनमित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करने के बाद पात्रतानुसार मुझे रकबा 0.325200 हैक्टेयर का कृषि भूमि पट्टा जारी किया गया। वनाधिकार पट्टा मिलने से उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने का रास्ता भी खुल गया। हितग्राही रूपबसंत द्वारा बैंक में जाकर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन दिया गया तथा नियमानुसार कार्यवाही के बाद उन्हें बैंक द्वारा केसीसी प्रदान किया गया। हितग्राही रूपबसंत ने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड बनने से अब उन्हें बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर कृषि कार्य खाद-बीज के साथ ही मवेशी खरीदने के लिए भी कृषि ऋण स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए हितग्राही रूपबसंत बताते हैं कि अब उन्हें साहूकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। किसान क्रेडिट कार्ड से रूपबसंत और उनके परिवार की समृद्धि एवं कृषि संबंधी वित्तीय जरूरतों के लिए सस्ता और सुविधाजनक वित्तीय समाधान मिला है जिससे कृषि उत्पादन भी बढ़ा है और आय भी।

संक्षिप्त समाचार

जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 26 दिसंबर को

रायसेन (निप्र)। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में 26 दिसंबर को शाम 04 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में संबंधित अधिकारी पूर्व माह में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में चाहे गए बिन्दुओं तथा पालन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरूण विश्वकर्मा की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित

रायसेन (निप्र)। निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन के संबंध में मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिसमें फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया गया। साथ ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप सूची की प्रतियां प्रदान की गई जिले में एसआईआर के पूर्व महातदाताओं की कुल संख्या 1041485 थी तथा एसआईआर के दौरान विलोपित मतदाताओं की संख्या 64796 है। प्रारूप प्रकाशन के दौरान मतदाताओं की कुल संख्या 976689 है। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज उपाध्याय भी उपस्थित रहे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरूण विश्वकर्मा की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित

रायसेन (निप्र)। निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन के संबंध में मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। जिसमें फोटो निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन किया गया। साथ ही मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप सूची की प्रतियां प्रदान की गई जिले में एसआईआर के पूर्व महातदाताओं की कुल संख्या 1041485 थी तथा एसआईआर के दौरान विलोपित मतदाताओं की संख्या 64796 है। प्रारूप प्रकाशन के दौरान मतदाताओं की कुल संख्या 976689 है। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज उपाध्याय भी उपस्थित रहे।

ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर बच्चों व महिलाओं को मिला स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ

सीहोर (निप्र)। जिले की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वी.एच.एन.डी.) के अवसर पर बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया। इस दौरान बच्चों का नियमित टीकाकरण एवं गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 01 वर्ष आयु वर्ग के 705 बच्चों का टीकाकरण किया गया, जबकि 01 वर्ष से अधिक आयु के 256 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही कुल 107 गर्भवती महिलाओं की जांच कर उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श एवं सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं।

सुशासन सप्ताह अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम जिले में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक प्रभावी रूप से पहुंचाने हेतु विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय स्थित रेवा सभा कक्ष में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।कार्यशाला में सुशासन से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर आधारित विभागीय नवाचारों की जानकारी संबंधित विभागों द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला पंचायत सीईओ श्री हिमांशु जैन ने की।

अस्पतालों में व्यवस्था बेहतर हो और मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाये- कलेक्टर

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक लेकर विकासखण्डवार स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की जानकारी ली। बैठक में दवाओं की उपलब्धता, विभिन्न जांच सुविधाओं, ओपीडी व्यवस्था तथा अस्पतालों में मरीजों को दी जा रही सेवाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें तथा जांच सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी न हो। ओपीडी व्यवस्था को और बेहतर बनाते हुए मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने कार्यों में प्रगति लाएं। एएनसी (गर्भवती) महिलाओं की नियमित ट्रेनिंग कराई जाए ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके। उन्होंने चिकत्सकों और स्वास्थ्य अमले से कहा कि किसी भी गर्भवती महिला की मृत्यु नहीं होना चाहिए।

उन्होंने अस्पतालों में साफ-सफाई, बैठने की व्यवस्था, पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं बेहतर करने पर भी जोर दिया गया। टीबी के संबंध में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि टीबी मरीजों की पहचान, उपचार एवं फॉलोअप में लापरवाही न बरती जाए तथा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत लक्ष्यों की समय पर पूर्ति सुनिश्चित की जाए। बैठक में सीएमएचओ श्री सुधीर डेहरिया सहित चिकित्सक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रदेश मे तेजी से विकसित हो रहा है सीहोर का बड़ियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र

औद्योगिक इकोसिस्टम और सरकारी सहयोग से एक आदर्श औद्योगिक हब बना रहा बड़ियाखेड़ी

सीहोर (निप्र)। राजधानी भोपाल से सटे सीहोर जिले का बड़ियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र आज प्रदेश के तेजी से विकसित होते औद्योगिक केंद्रों में अपनी अलग पहचान बना रहा है। कभी शांत ग्रामीण क्षेत्र रहा बड़ियाखेड़ी, अब रोजगार, निवेश और उद्यमिता का नया प्रतीक बन चुका है।

प्रदेश सरकार की उद्योग-हितैषी नीतियों, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं और ''जिला प्रशासन के सक्रिय सहयोग'' ने इस क्षेत्र के विकास को नई गति दी है। उद्योग संचालकों का कहना है कि भूमि आवंटन, अनुमति प्रक्रिया और प्रशासनिक मार्गदर्शन समयबद्ध व पारदर्शी रहा, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। आज बड़ियाखेड़ी में छोटे और मध्यम उद्योगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, इंजीनियरिंग, वेयरहाउसिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़े उद्योग यहां स्थापित हो रहे हैं। इसका सीधा लाभ स्थानीय लोगों को रोजगार के रूप में मिला है। आसपास के गांवों के अनेक युवा अब अपने ही जिले में काम पा रहे हैं, जिससे पलायन में कमी आई है।

खास बात यह है कि बड़ियाखेड़ी युवा उद्यमियों के लिए अवसरों का केंद्र बनकर उभरा है। कई युवा न केवल स्वयं रोजगार पा रहे हैं, बल्कि छोटे-छोटे उद्योग लगाकर दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। प्रशिक्षण, बैंकिंग सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर नई पीढ़ी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। बड़ियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फलो है जिसमें 141 उद्योगों प्लाट आवंटित किये जा चुके हैं। 32 उद्योग स्थापित हो चुके हैं और निरंतर संचालित हैं। सीहोर के पास ही मंडी औद्योगिक क्षेत्र में 11,पचामा औद्योगिक क्षेत्र में 20,आद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। इसके अलावा 10 से अधिक उद्योग निजी भूमि में स्थापित हैं। आईटीसी इंडस्ट्री के श्री अमित शर्मा, जगदम्बा पाइप इंडस्ट्री के श्री अंकित शर्मा तथा हम्बल काउ के संचालक श्री राम अवतार राय ने कहा कि उद्योग संचालकों का मानना है कि आने वाले समय में बड़ियाखेड़ी में विकास की अपार संभावनाएं हैं। राजधानी के नजदीक होना, बढ़ता औद्योगिक इकोसिस्टम और सरकारी सहयोग इसे एक आदर्श औद्योगिक हब बना रहा है। बड़ियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र आज इस बात का उदाहरण है कि सरकार, प्रशासन और उद्यमियों के साझा प्रयास से किस तरह क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक मजबूती हासिल की जा सकती है।

जिले के लोक सेवा केन्द्रों का एकजाई सघन निरीक्षण अभियान

आधार पंजीयन केन्द्रो में रेट लिस्ट का मुआयना

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशानुसार जिले में संचालित लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से निर्धारित दरों पर प्रदाय की जा रही सेवाओं एवं दस्तावेजों, विशेष रूप से आधार सेवा केन्द्रों, का निरीक्षण एक विशेष मुहिम के रूप में किया गया। इस अभियान के अंतर्गत राजस्व अधिकारियों द्वारा लोक सेवा केन्द्रों का परीक्षण सह जांच-पड़ताल कराई गई।

निरीक्षण के दौरान यह प्रमुख रूप से देखा गया कि लोक सेवा केन्द्रों में सेवाओं की निर्धारित दरों की रेट लिस्ट स्पष्ट रूप से चस्पा है या नहीं, ताकि आम नागरिकों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि न वसूली जा सके। इसके साथ ही केन्द्रों पर उपस्थित आवेदकों से सीधा संवाद कर सेवाओं के क्रियान्वयन, समयबद्धता एवं पारदर्शिता की क्रॉस मॉनिटरिंग भी की गई।

अधिकारियों द्वारा आधार पंजीयन, संशोधन एवं अन्य दस्तावेजी सेवाओं की प्रक्रिया, कार्य प्रणाली तथा आवेदकों को दी जा रही सुविधाओं का भी अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान जहां आवश्यक पाया गया, वहां केन्द्र संचालकों को निर्देश एवं आवश्यक समझाइश दी गई, ताकि शासन द्वारा निर्धारित मानकों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जा सके।

कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों को सरल, पारदर्शी एवं निर्धारित दरों पर सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। भविष्य में भी इस प्रकार के निरीक्षण अभियान निरंतर जारी रहेंगे, ताकि लोक सेवा केन्द्रों की कार्यप्रणाली में सुधार हो और नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

आधार नामांकन निःशुल्क एवं आधार अपडेट शुल्क के संबंध में बताया गया कि बायोमेट्रिक अपडेट नामांकित व्यक्ति का अपडेट बायोमेट्रिक्स फिंगर प्रिन्ट, आइरिस एवं फोटो के लिए यदि आवेदक यदि पांच से सात वर्ष की आयु के बीच एक बार बनाया जाता है तो निःशुल्क रहेगा। इसी प्रकार यह कार्य 15 से 17 वर्ष की आयु के बीच एक बार किया जाता है तो निःशुल्क संपादित किया जाएगा। सात से 15 वर्ष आयु के बीच 30 सितम्बर 2026 तक निःशुल्क सुविधा है अन्यथा 125 रूपए शुल्क देय होगा।

जन सांख्यिकी अद्यतन नामांकित कार्यो के तहत नाम, लिंक, जन्म तिथि, पता, मोबाइल नम्बर या ईमेल पता या इनमें से किसी भी संयोजन का अपडेशन कार्य करने के लिए एक बार समय सीमा में किया जाए तो बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क रहेगा। यदि अलग से उपरोक्त कार्य कराए जाएंगे तो 75 रूपए शुल्क देय होगी।

भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी की 101 वीं जयंती मनाई गई

कार्यकर्ताओं ने किया पुण्य स्मरण

कटनी। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय सहित जिले की चारों विधानसभाओं के मंडलों में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला कार्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन और राष्ट्रसेवा को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष एवं अटल स्मृति दिवस प्रभारी रवि खरे ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सहिष्णुता, संस्कार और लोकतांत्रिक मूल्यों की राजनीति के प्रतीक थे। उन्होंने राजनीति को गरिमा प्रदान की और भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाया। अन्य वक्ताओं ने अटल जी को केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक युग बताया। मीडिया प्रभारी आशुतोष शुक्ला एवं सचिन तिवारी ने कहा कि अटल जी का जीवन राष्ट्रप्रेम, लोकतांत्रिक मूल्यों और सेवा भाव का अनुपम उदाहरण है। उनके आदर्श और सुशासन की सोच आज भी समाज और कार्यकर्ताओं को देशसेवा के लिए प्रेरित करती है। कार्यालय मंत्री अम्बरीष वर्मा ने जानकारी दी कि अटल स्मृति दिवस के अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी के यशस्वी जीवन, राष्ट्रसेवा, विचारों और सुशासन की प्रेरक विरासत पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसका अवलोकन कार्यकर्ता एवं आमजन चार दिनों तक कर सकेंगे।

सुशासन सप्ताह के अंतर्गत सभी विभाग अपनी उत्कृष्ट गतिविधियां पोर्टल पर अपलोड करें - कमिश्नर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी

कमिश्नर ने संभागीय समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने संभागीय समय सीमा की बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह सुशासन सप्ताह के अंतर्गत अपनी विभागीय उत्कृष्ट गतिविधियां पोर्टल पर अपलोड करें। कमिश्नर ने कहा कि 25 दिसंबर तक सभी विभाग अपनी उत्कृष्ट गतिविधियां अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करेंगे। कमिश्नर श्री तिवारी ने बताया कि 25 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ग्वालियर में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के तहत करोड़ों के औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। नर्मदापुरम जिले की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का भी भूमि पूजन इस दौरान किया जाएगा। प्रदेश के हर संभाग में मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा।

कमिश्नर श्री तिवारी ने 17 अक्टूबर से प्रारंभ हुई दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के द्वितीय चरण की अदयतन स्थिति की समीक्षा की। बताया गया कि अभियान 30 दिसंबर तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत ऐसे पशुपालक जिनके पास 5 से 9 पशु होंगे उनसे संपर्क कर उन्हें पशु स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए जागरूक किया जाएगा। सभी पशुपालकों को उन्नत नस्ल के दुधारू पशु की देखरेख करने एवं दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 14 सौ पशुपालकों से संपर्क किया जाएगा। बताया गया कि सभी पशुपालकों की सूची बनाई गई है , जिनसे सतत संवाद किया जाएगा। इस दौरान पशुपालकों की वीडियो बाइट भी बना कर अन्य लोगों को दुग्ध उत्पादन लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत कमजोर नस्ल के पशुओं की नस्ल सुधार के लिए भी सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। साथ ही इस अभियान के अंतर्गत पशु पालको को दुग्ध उत्पादन से आय बढ़ाने के तरीके भी बताए जाएंगे।

कमिश्नर श्री तिवारी ने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए अधिक्षण यंत्री पीएचई को निर्देश दिए कि जिन नल जल योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है उसका 90 दिन का ट्रायल करके 90 दिन पश्चात नल जल योजना को ग्राम पंचायत को हैंडोवर कर दिया जाए, साथ ही जिन नल जल योजना का 90 दिन का ट्रायल आगामी दिनों में पूरा होना है उसकी भी सूची बनाकर ट्रायल के पश्चात उन सभी को ग्राम पंचायत को हैंडोवर कर सर्टिफिकेशन किया जाए। कमिश्नर श्री तिवारी ने सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने अधीनस्थ ब्लॉक एवं तहसील कार्यालयों मे शत प्रतिशत कार्य ई ऑफिस सिस्टम के तहत कराना सुनिश्चित करें।

कमिश्नर श्री तिवारी ने सभी संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने अधीनस्थ परिक्षाधीन अवधि पूर्ण करने वाले कर्मचारियों के इंक्रीमेंट एवं 20 से 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को समय मान वेतनमान देना सुनिश्चित करें।

कमिश्नर ने राजस्व संग्रहण करने वाले विभाग खनिज विभाग, नगरी निकायों, जिला परिवहन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आबकारी विभाग, जिला स्टांप व पंजीयन विभाग इत्यादि को अपने सभी राजस्व संग्रहण के लक्ष्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करने के निर्देश दिए।

ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था से साइबर अपराध पर शिकंजा

'सुशासन दिवस' पर मध्यप्रदेश पुलिस ने की अभिनव पहल

भोपाल। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस को 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाए जाने की परंपरा के अनुरूप, मध्यप्रदेश पुलिस ने सुशासन को सशक्त करने की दिशा में नवाचार के रूप में 'ई-जीरो एफआईआर' व्यवस्था प्रारंभ की है। यह व्यवस्था 01 लाख रुपये से अधिक की सायबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में लागू की गई है। 'ई-जीरो एफआईआर' व्यवस्था प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सायबर सुरक्षित भारत' विज़न के अनुरूप है, जिसका उल्लेख उन्होंने अक्टूबर 2024 में 'मन की बात' कार्यक्रम में किया था। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देशभर में सायबर अपराध से निपटने के लिये ऐतिहासिक एवं तकनीक-आधारित कदम उठाए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा ई-जीरो एफआईआर प्रणाली के क्रियान्वयन से यह स्पष्ट होता है कि तकनीक के माध्यम से न्याय प्रक्रिया को तेज और आम नागरिकों के लिए अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनाया जा सकता है। मध्यप्रदेश में लागू यह प्रणाली पुलिस को अपराधियों से एक कदम आगे रखने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। प्रदेश में बढ़ते सायबर अपराधों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तकनीक के दुरुपयोग से जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री का मानना है कि जिस प्रकार स्वच्छता को हमने अपनी संस्कृति बनाया है, उसी प्रकार सायबर स्वच्छता को भी जन-आंदोलन बनाना होगा। प्रदेश में ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था का संचालन पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री ए. साई मनोहर के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस को अधिक तेज, तकनीक-सक्षम और नागरिक-केंद्रित बनाना है।

साइबर वित्तीय धोखाधड़ी पर प्रभावी प्रहार–साइबर वित्तीय धोखाधड़ी आज पुलिस के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। कई बार पीड़ित की जीवनभर की कमाई कुछ ही क्षणों में अपराधियों के हाथों में चली जाती है, जिससे वह स्वयं को असहाय महसूस करता है। इसी पीड़ा को समझते हुए गृह मंत्रालय द्वारा 'ई-जीरो एफआईआर' की अवधारणा लागू की गई है, ताकि तकनीक को अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी हथियार बनाया जा सके। जुलाई 2024 से लागू हुए नए आपराधिक कानून 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (बीएनएसएस) नागरिक-केंद्रित हैं। इनका मूल उद्देश्य 'दंड नहीं, बल्कि न्याय' पर फोकस रहना है। बीएनएसएस की धारा 173 के अंतर्गत 'जीरो एफआईआर' को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है, जिससे नागरिक देश में कहीं से भी, किसी भी क्षेत्राधिकार में घटित अपराध के लिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

ई-जीरो एफआईआरः एक क्रांतिकारी व्यवस्था–'ई-जीरो एफआईआर' सायबर वित्तीय धोखाधड़ी–विशेषकर रू. 1 लाख से अधिक की हानि के मामलों में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया को अत्यंत तेज बनाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाओं को समाप्त कर जांच प्रक्रिया को तत्काल प्रारंभ करना है। यह प्रणाली तीन प्रमुख डिजिटल मंचों का एकीकरण करती है। नेशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी), I4सी (भारतीय सायबर अपराध समन्वय केंद्र) और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस)।

ई-जीरो एफआईआर पंजीकरण की 5-चरणीय प्रक्रिया– शिकायत दर्ज करना - पीड़ित 1930 हेल्पलाइन या NCRP पोर्टल पर शिकायत करता है। रू. 1 लाख से अधिक की धोखाधड़ी होने पर डेटा सीधे भोपाल स्थित केंद्रीय सायबर पुलिस हब को भेजा जाता है। ऑटोमैटिक जनरेशन - सीसीटीएनएस सर्वर के माध्यम से शिकायत स्वतः 'ई-जीरो एफआईआर' में परिवर्तित हो जाती है।

पीड़ित को तुरंत 'ई-जीरो एफआईआर' नंबर उपलब्ध कराया दिया जाता है। समीक्षा एवं हस्तांतरण - राज्य स्तरीय सायबर पुलिस स्टेशन द्वारा समीक्षा कर प्रकरण संबंधित क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन को भेजा जाता है। नियमित एफआईआर में परिवर्तन- शिकायतकर्ता को 3 दिन के अंदर नजदीकी सायबर पुलिस स्टेशन में 'ई-जीरो एफआईआर' को नियमित एफआईआर में परिवर्तित कराना होता है।

साइबर अपराध में 'गोल्डन ऑवर' का महत्व

सायबर अपराध में धोखाधड़ी के बाद के पहले 2 घंटे को 'गोल्डन ऑवर' माना जाता है। यदि पीड़ित तुरंत 1930 पर संपर्क करता है, तो I4C एवं बैंकों के सहयोग से अपराधी के खाते में राशि पहुंचने से पहले ही उसे फ्रीज किया जा सकता है। ई-जीरो एफआईआर के माध्यम से आईपी लॉग, ट्रांजैक्शन आईडी जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य तत्काल और कानूनी रूप से सुरक्षित किए जाते हैं।

'ई-जीरो एफआईआर' व्यवस्था के प्रमुख लाभ

'ई-जीरो एफआईआर' व्यवस्था देश में कहीं से भी कहीं भी हुई सायबर या वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। इससे क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलती है, केस की स्थिति ऑनलाइन देखने की सुविधा मिलती है, शीघ्र एफआईआर से बैंकिंग चैनल सक्रिय, हो जाते हैं, राशि वापसी की संभावना अधिक हो जाती है साथ ही पोर्टल पर सीधे स्क्रीनशॉट और रसीदें अपलोड करने की सुविधा मिलने से आवश्यक दस्तावेज हमेशा उपलब्ध बने रहते हैं।

नए साल में 2-3 जनवरी को भोपाल में मोहन भागवत

युवा संवाद और प्रबुद्धजनों से चर्चा करेंगे, जेपी नड्डा शनिवार को कटनी आएंगे

भोपाल। नए साल की शुरुआत मध्यप्रदेश में राजनीतिक और वैचारिक गतिविधियों के साथ होने जा रही है। राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) अपने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में चार बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिनमें संघ प्रमुख मोहन

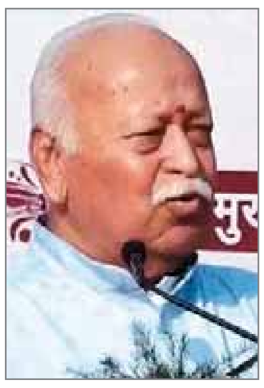

भागवत समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करेंगे। वहीं, प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कटनी में मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन करेंगे। नए साल की शुरुआत में आरएसएस चार बड़े वैचारिक और सामाजिक संवाद कार्यक्रमों करने जा रहा है। 2 और 3 जनवरी को आयोजित इन कार्यक्रमों में संघ प्रमुख (सरसंघचालक) मोहन भागवत समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद करेंगे। इन आयोजनों के माध्यम से संघ अपने 100 वर्ष पूरे होने के बाद देश और समाज के लिए भविष्य की दिशा और भूमिका को सार्वजनिक रूप से सामने रखेगा। संघ के कार्यक्रमों की शुरुआत 2 जनवरी को होगी। इस दिन दो प्रमुख आयोजन होंगे। पहला युवा संवाद, जिसमें मोहन भागवत भारत को विश्व पटल पर संगठित, सशक्त और समर्थ राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में युवाओं की भूमिका पर अपना व्याख्यान देंगे। इस संवाद की विशेषता यह होगी कि भागवत युवाओं के सवालों के सीधे जवाब भी देंगे। इसी दिन प्रबुद्ध जन गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मध्य भारत प्रांत ग्वालियर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग से एक हजार से अधिक प्रतिष्ठित, प्रभावशाली और समाज के अग्रणी लोगों को आमंत्रित किया गया है। 3 जनवरी को दो अन्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। पहला सामाजिक सद्भाव सम्मेलन, जिसमें मोहन भागवत देश में सक्रिय विभाजनकारी ताकतों और उनके षड्यंत्रों पर संघ का दृष्टिकोण स्पष्ट करेंगे। दूसरा शक्ति (महिला) संवाद कार्यक्रम होगा, जिसमें देश की राजनीति और सामाजिक जीवन में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर संघ की सोच और दिशा को सामने रखा जाएगा।

ग्वालियर की धरा से मध्यप्रदेश ने पूरे देश को दिया विकास का नया संदेश

मध्यप्रदेश बना सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाला राज्य : शाह

भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मध्यप्रदेश अब देश में सबसे तेज़ गति से विकास करने वाला राज्य बन गया है। बीते सालों की वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव से अलग रहकर अनेकानेक चुनौतियों और संसाधनों के अभाव से उबरकर प्रदेश ने जिस रफ्तार से प्रगति की है, वह पूरे देश को अभिप्रेरित करती है। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सुधार, खनन, फार्मा, नवकरणीय ऊर्जा और वृहद संख्या में आधारभूत अवसंरचनाएं, हर क्षेत्र में मध्यप्रदेश आज अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने अपनी नई सोच, उद्यमशीलता, प्रगतिशील दृष्टिकोण और नवाचारों के माध्यम से विकास के ऐसे मानक स्थापित किए हैं, जिनका अनुसरण अब अन्य राज्य भी कर रहे हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह गुरुवार को भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जयंती के विशेष अवसर पर ग्वालियर के मेला मैदान में आयोजित 'अभ्युदय मध्यप्रदेश ग्रोथ समिट' को संबोधित कर रहे थे।

श्री अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता उसकी भौगोलिक स्थिति है। आधे भारत को यहाँ से बहुत कम परिवहन लागत से सप्लाई किया जा सकता है, लेकिन उसका शत-प्रतिशत दोहन तभी हो सकता है जब मध्य प्रदेश में उद्योग symmetrically लगें। दक्षिणी राज्यों से सटे जिलों में, दिल्ली से सटे क्षेत्रों, जैसे ग्वालियर, में उद्योग लगे, पश्चिम से सटे क्षेत्रों, जैसे धार और झाबुआ में भी उद्योग लगे, तभी भौगोलिक स्थिति का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की क्षेत्रीय निवेश समिट ने राज्य के चहुँमुखी विकास की नींव डालने का काम किया है। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि यहाँ ग्वालियर से जुड़े 14 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन हुआ।

अटलजी राष्ट्रनीति के शिखर पुरूष एवं राजनीति के अजातशत्रु थे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार ने उद्योग एवं रोजगार वर्ष में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। श्रद्धेय अटल जी राष्ट्रनीति के शिखर पुरुष एवं राजनीति के अजातशत्रु थे। मुख्यमंत्री ने स्व. अटल जी की 101वीं जयंती के अवसर पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में गरीब, किसान, महिला एवं युवाओं के कल्याण के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश इसी 11 दिसंबर को नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतः मुक्त हो चुका है। हमारी सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिये हर संभव कोशिश कर रही है। मध्यप्रदेश में 8.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर रहे हैं। अटलजी की जयंती के अवसर पर प्रदेश के साथ-साथ ग्वालियर को भी बड़ी सौगातें मिल रही हैं।

प्रदेश के स्कूलों में आज मनेगा वीर बाल दिवस

- स्कूलों में होंगी चित्रकला एवं लेखन प्रतियोगिताएं
- मंत्री ने की प्रतियोगिता में शामिल होने की अपील

भोपाल। प्रदेश के स्कूलों में 26 दिसम्बर को वीर बाल दिवस मनाया जायेगा। इसके लिये स्कूल शिक्षा विभाग ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने स्कूल के बच्चों से इस दिन होने वाली गतिविधियों में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह द्वारा दिये गये सर्वोच्च बलिदान के संबंध में प्रतिवर्ष 26 दिसम्बर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के भविष्य की नींव माने जाने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिये समर्पित एक राष्ट्रीय उत्सव है। इस पहल का उद्देश्य युवा प्रतिभाओं का पोषण करना, रचनात्मकता को बढ़ावा देना और उन्हें विकसित भारत के सपने में योगदान देने के लिये प्रेरित करना है।

राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का होगा सजीव प्रसारण– वीर बाल दिवस का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम 26 दिसम्बर, 2025 को दोपहर 12:30 बजे भारत मण्डपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण (लाइव वेबकास्ट) पर किया जायेगा। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि इस लिंक की सूचना सभी सरकारी और प्रायवेट स्कूलों में दी जाये, जिससे स्कूल के विद्यार्थी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकें। जिला शिक्षा अधिकारियों को दिये गये निर्देश में कहा गया है कि इससे जुड़ी जानकारी साझा की गई है।

वीर बाल दिवस पर होने वाली प्रतियोगिताएं– स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में आयु समूह के अनुसार विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित करने का निर्णय लिया है। आयु वर्ग 3-6 वर्ष के लिये चित्रकारी, पेंटिंग, खेल गतिविधियाँ एवं कहानी सुनाना और आयु वर्ग 6-10 वर्ष के लिये चित्रकला, निबंध लेखन एवं कहानी सुनाना प्रमुख हैं। इसके लिये जो विषय तय किये गये हैं, उनमें मेरे सपनों का भारत, वह भारत जो मैं देखना चाहता हूँ, दूसरों की मदद करना मेरी महाशक्ति है, मेरी संस्कृति के रंग और मेरे आसपास के नायक, जिनमें शिक्षक, देखभालकर्ता और मित्र शामिल हैं। स्कूलों में आयु वर्ग 11-18 वर्ष के लिये निबंध, कविताएँ, वाद-विवाद और डिजिटल प्रतियोगिता शामिल हैं। इनके लिये जो विषय तय किये गये हैं, उनमें 'राष्ट्र निर्माण में बच्चों की भूमिका', 'विकसित भारत के लिये मेरा दृष्टिकोण', 'विकसित भारत बनाने में बच्चों की भूमिका', 'विकासशील भारत को आकार देने में बच्चों की भूमिका', 'साहस और करुणा, एक नायक क्या बनाता है', 'भारत के इतिहास में वीरता की कहानियाँ', 'डिजिटल इण्डिया में युवाओं के लिये अवसर', 'स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत', 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ', 'प्रत्येक बालिका को सशक्त बनाना' शामिल हैं। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत-नवाचार में युवाओं की अग्रणी भूमिका, 'वोकल फॉर लोकल', 'भारत की पारम्परिक शिल्प-कलाओं का उत्सव मनाना', 'स्किल इण्डिया मिशन' और 'अमृतकाल में कल के भारत निर्माण में युवाओं की भूमिका' को शामिल किया गया है।

दमोह में क्रिकेट में जीत का मतलब...दो बेटियों की शादी

● पहली संतान बेटी हुई तो कराने लगे 'विवाह क्रिकेट टूर्नामेंट' ● फाइनल मैच में आएगी बारात,अब तक चार बेटियों की शादी

दमोह। दमोह के कुम्हारी गांव में इन दिनों एक ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, जो सिर्फ रन और विकेट की बात नहीं करता, बल्कि गरीब और अनाथ बेटियों के जीवन की नई पारी लिख रहा है। यह कोई आम टूर्नामेंट नहीं, बल्कि 'विवाह क्रिकेट टूर्नामेंट' है, जहां फाइनल मैच में बारात आएंगी और दो बेटियों का विवाह कराया जाएगा। मकर संक्रांति के बाद खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में जीत-हार से ज्यादा अहम होगा वो पल, जब समाज के सहयोग से दो जरूरतमंद बेटियां सम्मानजनक जीवन की शुरुआत करेंगी। इस अनोखी पहल के पीछे हैं कुम्हारी गांव के निवासी रवि चौहान। रवि बताते हैं- 'मेरी पहली संतान बेटी है और मैंने दूसरी भी बेटी ही चाही। बेटा-बेटी में कोई फर्क नहीं होता, इसी सोच से हर साल एक जरूरतमंद बेटी की शादी कराने का संकल्प लिया। रवि की यह सोच आज पूरे गांव और आसपास के समाज को जोड़ रही है। परिवार, मित्र और समाजसेवी इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।'

दो सीजन, दो बेटियों की नई शुरुआत– 2023: पहले सीजन में कुम्हारी गांव की बेटी रानी आदिवासी का विवाह फाइनल मैच के दौरान कराया गया। दहेज की जगह समाजसेवियों ने गृहस्थी का जरूरी सामान भेंट किया। 2024: दूसरे सीजन में बबीता आदिवासी का विवाह संजय नगर गैसाबाद निवासी युवक से संपन्न हुआ। इस आयोजन को समाज का जबरदस्त समर्थन मिला। इस साल फिर दो बेटियों के हाथ पीले होंगे।

इस बार दो दलित-आदिवासी बेटियों का विवाह– रवि चौहान बताते हैं कि 2025 में भी दो जरूरतमंद बेटियों की शादी की तैयारी चल रही है। एक बेटी दलित परिवार से है और दूसरी बेटी आदिवासी परिवार की है। इनके विवाह का पूरा खर्च टूर्नामेंट से जुटी राशि और समाजसेवियों के सहयोग से किया जाएगा। कुम्हारी गांव का यह टूर्नामेंट बताता है कि खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं, समाज बदलने का जरिया भी बन सकता है। जहां आमतौर पर क्रिकेट में ट्रॉफी मिलती है, वहीं यहां बेटियों को सम्मान, सुरक्षा और भविष्य मिल रहा है। टूर्नामेंट के आयोजक रवि चौहान ने बताया कि विवाह के लिए आर्थिक स्थिति कमजोर वाले परिवार को चुनते हैं। टीम के सदस्य उनके घर जाकर देखते हैं। उसके बाद उन्हें कहा जाता है। घर का सामान पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। फाइनल मैच के दिन ग्राउंड पर जयमाला डलवाई जाती है। इसके बाद उनके घर बाकी रस्में की जाती हैं। रवि के पिता हटा में सरकारी टीचर हैं। साथ ही, पैतृक जमीन भी है। बड़े भाइयों का इंदौर में मेडिकल स्टोर है। वह चाहते हैं कि जितना हो सके, गरीब और अनाथ बेटियों की मदद करते रहें। इस बार 20 दिसंबर से टूर्नामेंट शुरू हो गया है। इसमें जिले भर की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। एक दिन छोड़कर मैच होता है। 15 फरवरी 2026 को फाइनल मैच होगा। मैच के बाद बेटियों की शादी करवाई जाएगी।